RNI No. : DELBIL/2021/79984 ₹ 20

# सीमा संघोष

सितम्बर 2023

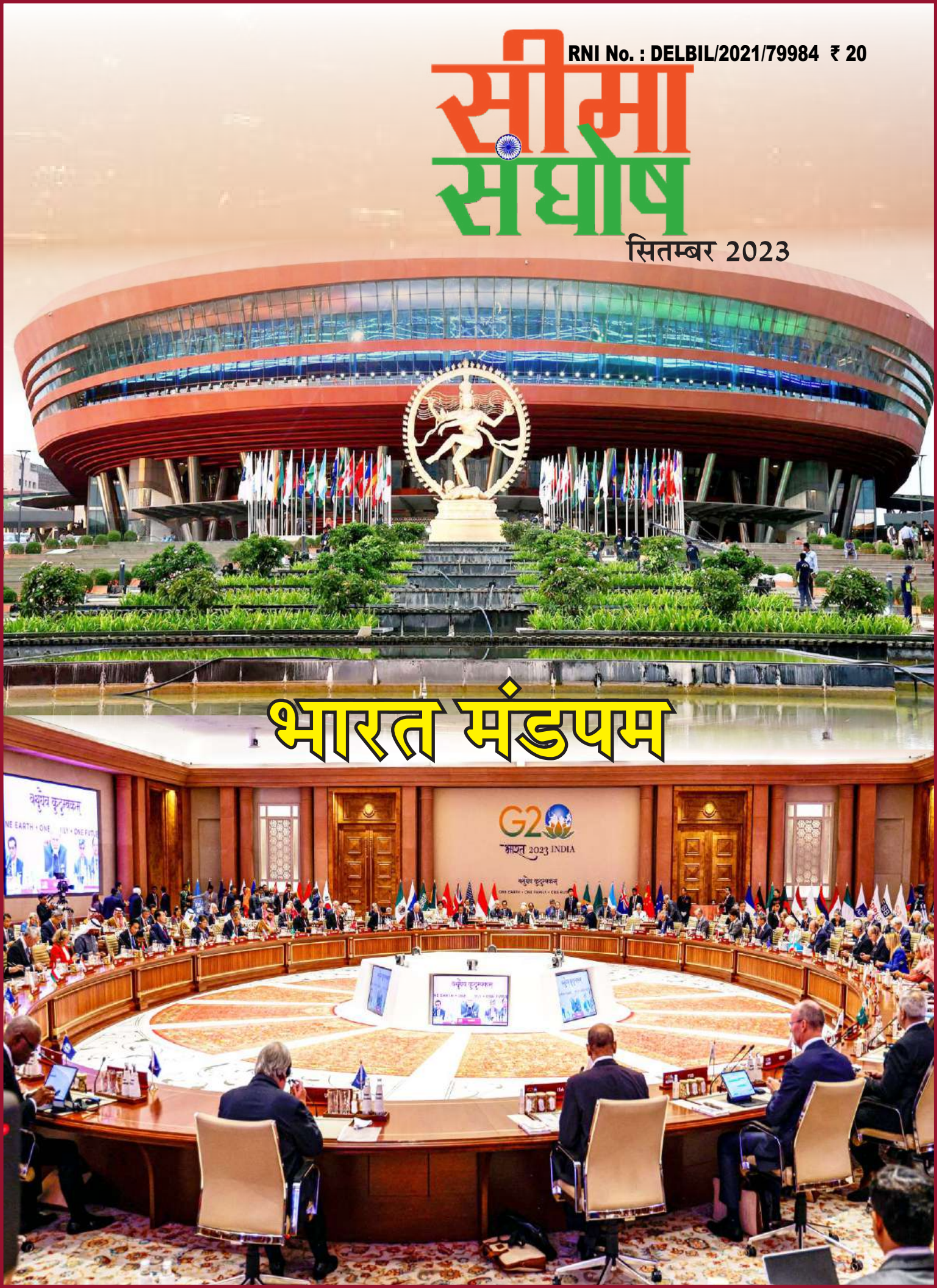



## भारत मंडपम

# नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

संरक्षक – प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा
मुख्य सलाहकार – ब्रिगेडियर कपिल देव मल्होत्रा
प्रबंध संपादक – श्री रविन्द्र अग्रवाल

मुख्य संपादक – दीपांशु गर्ग
कार्यकारी संपादक – डा. प्रदीप कुमार
संपादक मंडल – श्री राजीव रंजन
– प्रो. चन्द्रवीर सिंह भाटी
– श्री अयोध्या प्रसाद
– डा. राहुल मिश्र

डिजिटल प्रमुख – धीरज झा
डिजाइनिंग – वीरेन्द्र

## प्रधान कार्यालय

सीमा संघोष
43/21, तृतीय तल, ईस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली-110008, फोन : 9811702522
website : https://seemasanghosh.org/menu.php
e-mail : sanghoshofficial@gmail.com

Published & Printed by Vinay Gupta
On behalf of SEEMA SANGHOSH
Printed at B K offset F- 93,
Panchsheel Garden, Navin Shahdara
Delhi-110032. Publish From 43/21
3rd Floor, East patel Nagar, New
Delhi 110027

प्रकाशकों और लेखकों ने सीमा संघोष की सामग्री के संबंध में अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं। प्रकाशकों की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर कोई भी कॉपीराइट कार्य किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहां उपयोग की गई छवियां सार्वजनिक डोमेन से हैं, उनके संबंधित स्वामियों की हैं और केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए यहां उपयोग की जा रही हैं। यह पत्रिका गैर-व्यावसायिक, गैर लाभदायक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य लेकर प्रस्तुत की गयी है।

# इस अंक में

भारत के वैश्विक प्रभावों का स्वीकरण है
**G-20** शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन - राजीव रंजन प्रसाद -05

ट्रूडो की भारत विरोधी मुहीम - पुनीत अरोड़ा - 13

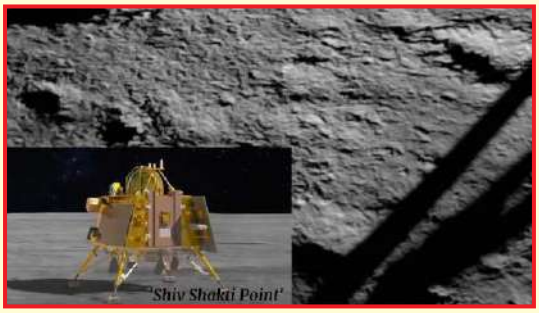


'शिव-शक्ति प्वाइंट'
हिंदू प्रेरणा के हस्ताक्षर हैं, चंद्रमा पर! - युवराज पलवल - 17

◘ भारत में जीवन का केंद्र है 'स्त्री' – डॉ. प्रताप निर्भय सिंह.....09

◘ हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान कब ? –डॉ. नरेन्द्र टोंक .....12

◘ 'मणिपुर घटना : शांति के प्रयास और भविष्य की सीख'
– मनोहर दान .....15

हिंदू तीर्थ स्थानों के व्यापारिक प्रतिस्थापनाओं पर मुस्लमान बाहुल्य
– राजेश्वर सिंह 'राजू'.....19

◘ सनातन धर्म को खत्म करने की महत्वाकांक्षा! – .....22

◘ रक्षा समाचार – .....24

◘ सीमा संवाद श्रृंखला रिपोर्ट – राघवेन्द्र नाथ त्रिपाठी.....27

◘ सीमा विमर्श – आशीष केसरवानी.....30

# संपादकीय.....

भारत ने विकसित देश हो जाने की अपनी यात्रा आरंभ कर दी है, इसके लिए मील का पत्थर है - नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित सफल जी 20 सम्मेलन। यह आयोजन भारत की अप्रतिम कूटनीति का ही नहीं अपितु संस्कृति, सभ्यता और संभावनाओं का भी वैश्विक प्रदर्शन सिद्ध हुआ है। जिस तरह से इस आयोजन के दौरान 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को सर्व सम्मति से जारी करने में सफलता मिली, यह प्रदर्शित करता है कि भारत की बात दुनिया में ध्यान से सुनी जा रही है। इस बात का लिटमस टेस्ट भी तब हुआ जब एक ओर तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगा रहे थे वहीं दूसरी ओर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन करने पर उन्होंने खरी खरी भी सुना दी। कनाडा के नागरिक हो चुके वे सिख भारतीय मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी का अधिकार नहीं रखते जो हमारी भूमि के लिए अलगाववादी मानसिकता रखते हैं। किसी विदेशी नागरिक का भारत के आंतरिक मामलों में बोलना और आंदोलन करना न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है न ही उचित, बल्कि इस पर रोक न लगा पाना स्पष्ट रूप से कनाडा की राजनैतिक मजबूरी को परिलक्षित करता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत में ठंडा स्वागत मिला जिस कारण उनकी अपने ही देश में अत्यधिक आलोचना हुई। एक कनेडीयाई अखबार ने तो दोनों प्रधानमंत्रियों की ऐसी तस्वीर प्रकाशित की जिसमें नरेंद्र मोदी हाथ के इशारे से जस्टिन ट्रूडो को सम्मेलन कक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं तथापि शीर्षक बनाया गया था "दिस वे आउट"। करेला उस पर नीम चढ़ा वाली स्थिति तब पैदा हो गई जबकि जले भुने बैठे जस्टिन ट्रूडो का विमान भारत में खराब हो गया और उसके ठीक होने तक कनेडियाई प्रधानमंत्री को अगले कुछ दिन होटल में बैठे रह कर भारत में बिताने पड़े। भारत द्वारा अपना विमान दिए जाने की पेशकश का उनके द्वारा ठुकराया जाना भी आश्चर्य की बात थी यही नहीं खबरें यह भी निकाल कर आई कि जी 20 समिट के लिए आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के ठहरने लिए होटल में जिस प्रेसिडेनशियल सूट की व्यवस्था भारत की ओर से की गई थी इसका अस्वीकार कर जस्टिन ट्रूडो अलग और सामान्य कमरे में ठहरे। वस्तुतः यह कनेडियाई प्रधानमंत्री का नाराजगी दिखाने का तरीका था और यह बात साफ साफ नजर आ रही थी कि वापस लौटने के बाद कोई न कोई कूटनीतिक प्रतिवाद देखने को अवश्य मिलेगा।

गली मुहल्ले की राजनीति जैसी हरकत करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने संसद का दुरुपयोग किया और वहाँ खड़े हो कर साक्ष्यों के बिना ही भारत पर आरोप लगा दिया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर जोकि अब कनाडा का नागरिक था, इसकी हत्या में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। इस आरोप के बाद भारत-कनाडा संबंध तो अपने सबसे बुरे दौर में प्रविष्ट हुए ही, साथ ही पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो मजाक का विषय बन गए। वे ऐसे राजनेता सिद्ध हुए जिन्हें यह पता नहीं कि दो देशों के बीच कूटनीति कैसे कार्य करती है अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे आगे ले जाया जाता है। इसके उलट भारत को यह लाभ हुआ कि कनाडा की वास्तविकता को पूरी दुनिया ने जाना। भारत सिद्ध कर सका कि किस तरह कनाडा की भूमि का भारत में अलगाववादी गतिविधियां चलाने वाले कुख्यात आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि कनाडा आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पाकिस्तान के बाद कनाडा दूसरा ऐसा देश है जिसके लिए भारत ने ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग किया है। जो कदम उठाए गए जैसे प्रतिवाद में कनाडा के राजनयिक को बाहर निकाल देना या कि वहाँ के नागरिकों के लिए वीजा बंद कर देना, इससे यह संदेश ही गया कि भारत उभरती हुई महाशक्ति है और वह पश्चिमी देशों के दबाव में आने वाला नहीं है।

कनाडा प्रकरण में पश्चिमी देशों का दोहरा मानदंड ही सामने आया है जहाँ उनके देश में हुई आतंकवादी गतिविधि के लिए मापदंड अलग हैं और उनके ही देश से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए बिलकुल अलग। प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान में घुस कर सैन्य कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा मारा जाना पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला नहीं था? एबटाबाद पर अमेरिकी हमले के असंख्य साक्ष्य हैं यहाँ तक कि स्वयं अमेरिका ने इस बात को स-गर्व स्वीकार किया है। इस उदाहरण को सामने रखा कर सोचें कि कनेडियाई नागरिक और आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात लोगों द्वारा की गई हत्या को भारत से जोड़ने के असफल प्रयास के दौरान दोहरे मानदंड कैसे हो सकते हैं? कोई परिघटना अमेरिका करे तो ही सही होगी यह तो उचित तर्क नहीं है? भारत को विदेशी धरती पर हत्याएं करने की आवश्यकता ही नहीं है आतंकवादी ऐसा कोढ होते हैं जिन्हे अपनी मौत स्वयं ही मर जाना है।

आपका ही
राजीव रंजन प्रसाद

# भारत के वैश्विक प्रभावों का स्वीकरण है G-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन

**राजीव रंजन प्रसाद**
उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण) एनएचपीसी लि.

भारत ने जी 20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के द्वारा अपनी वैश्विक पहचान निर्मित की है। औपचारिक रूप से जी 20 सदस्यों की वार्षिक बैठक को 'जी 20 शिखर सम्मेलन' कहा जाता है जोकि 9–10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित हुई। जी 20 के सदस्यों में उन्नीस देश अर्थात् भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका सम्मिलित हैं, साथ ही इस समूह का बीसवां सदस्य है यूरोपियन यूनियन। यह समूह इसलिए महत्व का है क्योंकि जी 20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कुल मिला कर दुनिया की दो–तिहाई आबादी के भी प्रतिनिधि हैं। भारत ने इस वर्ष बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशिस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई आदि देशों को अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था।

इससे पूर्व कि जी–20 सम्मेलन में आए विविध राष्ट्राध्यक्षों, उनकी अपेक्षाओं, अभिव्यक्ति और उनके द्वारा किए गए विमर्शों की विवेचना हो, पहले आयोजन स्थल अर्थात् भारत मंडपम की बात करते हैं। भारत आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अतः जहाँ हमारी भूमि, वैश्विक अतिथियों का स्वागत करेगी वह स्थल इसी अनुरूप भव्य होना चाहिए, साथ ही हमारी संस्कृति के अनुरूप भी होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने प्रगति मैदान को चुना, यहाँ बने इंटरनेशनल एग्जिबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को लगभग सत्ताईस सौ करोड़ रुपये की लागत से न केवल नये रूप–रंग में ढाल दिया अपितु नया नाम भी दिया – भारत मंडपम। भगवान बसेश्वरा के 'अनुभव मंडपम' से प्रेरित होकर यह 'भारत मंडपम' नामकरण किया गया है। भारत मंडपम का आकार शंख की तरह है, साथ ही दीवारों पर सूर्य शक्ति, जीरो टू इसरो, पंच महाभूत और

अन्य विषयों को भी रेखांकित किया गया है। भारतीय इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जोकि सिडनी के ऑपेरा से भी बड़ा है। जितना बडा आयोजन, उतना ही भव्य आकार प्रकार अर्थात् भारत मण्डपम एक सौ तेईस एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें हर कक्ष, हर सभागार में भारतीय संस्कृति की झलख दिखाई पड़ती है। वैश्विक सम्मेलनों को आयोजित करने के अनुरूप इसमें बैठक कक्ष, लॉन्ज, ऑडिटोरियम, एम्पीथियेटर, बिजनेस सेंटर सहित अनेक अन्य सुविधाएं हैं। इसका मुख्य सभागार एक साथ सात हजार लोगों को समाहित कर सकता है साथ ही एम्पीथियेटर में भी तीन हजार लोगों के बैठने की सुविधा है। यह आयोजन स्थल भारतीयता को उसकी पुरातनता के साथ भी सामने लाता है और आधुनिक स्वरूप को भी सुस्पष्ट करता है, अर्थात यह 5–जी वाइफाइ से परिपूर्ण कैम्पस है; बैठक कक्षों में सोलह भाषाओं के परस्पर अनुवाद होने की सुविधा उपलब्ध है। इस भवन में वीडियो वॉल, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सेंटर आदि सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

भारत में कुछ बेहतर हो या निर्मिति की जाये और 'मीन–मेख निकालने वाला समूह लुटियन समूह' सक्रिय न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। ऐन जी–20 के

मुख्य आयोजन से पहले भारत मंडपम के सामने नटराज की सत्ताईस फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। चूँकि नटराज सनातन मानयताओं से सम्बद्ध हैं, वाम–कलमों ने आलोचना में अखबार रंग दिए। यह भारत की प्रबुद्ध जनता है जो जानती है कि ऐसी कुत्सित प्रतिक्रियाओं को किस कूड़े के ढेर में पटकना है। इस प्रतिमा को देश–विदेश में अत्यधिक सराहना मिली। नटराज की यह भव्य प्रतिमा अष्ट धातु अर्थात् सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, लोहा, पारा और सीसा से निर्मित है। इसके बनाने की प्रक्रिया में कावेरी नदी से निकाली गई मिट्टी का भी उपयोग किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा को उसी परिवार के वंशजों ने बनाया है जिन्होंने चोल राजवंश के शासन समय में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की विश्वप्रसिद्ध नटराज प्रतिमा निर्मित की थी।

इस आयोजन के दौरान ही एक और विवाद चरम पर था अर्थात् यह कि क्या सरकार "इंडिया" नाम को चलन से बाहर कर केवल "भारत" को ही देश के नाम के रूप में स्वीकृत करना चाहती है? इस बहस के गरमाने का प्रमुख कारण था कि जी–20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में "प्रेसिडेंट ऑफ भारत" तथा आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री के नामपट्ट पर "प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत" कहकर संबोधित किया गया था। भारत तो संविधान सम्मत नाम है इसे यदि प्राथमिकता से चलन में लाया जा रहा है तो किसी को भी कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? हमारा संविधान हमें अवगत कराता है कि "इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा" अर्थात् भारत सहित इंडिया भी इस देश का नाम है। हमारा राष्ट्रगान "भारत भाग्य विधाता?" तक सीमित रखा गया है, क्यों? हमारा राष्ट्रीय गीत जिन्हें "सुहासिनीं, सुमधुर भाषिनीम्, सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्" कह रहा है उन भारत माता को इंडिया परिभाषा के अंतर्गत कल्पित करना कठिन लगता है। इसलिए "भारत" नाम अपनी पुरातनता और देशजता के कारण प्रयोग के लिए सर्वथा उचित है। इंडिया शब्द प्राचीन यूनानी सभ्यता का दिया है, वे लोग सिंधु

नदी को इंडस कहते थे, जिससे इंडिया बना है। यहाँ से ही इंडस और इंडिया शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा। इसी नाम का उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भी बढ़ावा दिया। जबकि भारत नाम को विष्णु पुराण के इस उद्धरण से समझा जा सकता है कि "उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेचैव दक्षिणम ध्य वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति"। अर्थात् भारत नाम ही भारत देश की पुरातन पहचान है। अब सोचिए कि क्यों बर्मा से म्यानमार हुआ, सीलोन से श्रीलंका हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ, चेक गणराज्य से चेकिया हो गया, टर्की से तुर्किये हो गया, सियाम से थाईलैंड हो गया या कि फारस से ईरान हो गया? इन देशों ने अपनी सांस्कृतिक हलचल को वरीयता दी है फिर "भारत" नाम को वरीयता क्यों नहीं देनी चाहिए?

विवादों के बाद भी भारत ने जी–20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कर विश्व को चकाचौंध कर दिया था। एक वर्ष तक जी–20 देशों की अध्यक्षता भारत के पास रही और सरकार ने इसे लोक–उत्सव में बदल दिया था। लगभग नौ माह के अंतराल में भारत के साठ से अधिक नगरों में दो सौ सम्मेलन हुए। भारत ने अपनी कूटनीति की धार को पैना करते हुए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी कार्यक्रम सम्पन्न करवा कर दुनिया को यह बताया कि चाहे वह पाकिस्तान का प्रोपेगेन्डा हो अथवा चीन का, ये परिक्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं। कश्मीर में तो पर्यटन विषयक आयोजन न हो सके इसके लिए पाकिस्तान ने अपने तौर से एडी–चोटी का जोर लगा लिया था। कुछ–एक मुस्लिम देशों के अतिरिक्त सभी देशों के प्रतिनिधि न केवल कश्मीर आए बल्कि उनके माध्यम से पूरी दुनिया को वहाँ की वस्तुस्थिति का सही आँकलन प्राप्त हुआ। अब बारी शिखर सम्मेलन की थी जोकि 9–10 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम में आयोजित हुआ। यद्यपि निजी कारणों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो सके तथापि उनके स्थान पर प्रतिनिधि इसमें प्रतिभागिता करने पहुंचे थे। जिस तरह से भारत ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का भव्य स्वागत किया यह दुनियाँ के अखबारों की सुर्खियां भी बना। यद्यपि इस बैठक का कोई तय एजेंडा नहीं था तथापि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियां, रूस–यूक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और ग़रीबी जैसे मुद्दे चर्चा का हिस्सा बने थे।

अब यह जी–20 भारत में आयोजित होने के बाद से जी–21 देशों के समूह के रूप में बदल गई है क्योंकि दिल्ली समिट में अफ्रीकन यूनियन इसका नया सदस्य समूह बनाया गया है। वैश्विक सम्मेलनों में भी भावुक दृश्य देखने को मिलें तो वह स्थान भारत में ही हो सकता है। जैसे ही जी 20 बैठक में शामिल होने नई दिल्ली आए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा को यह सूचना प्रदान की गई कि सर्व सम्मति से अफ्रीकी संघ को अब जी–20 की सदस्या प्रदान की गई है, वे अपना स्थान लेने से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़े और दोनों नेताओं ने गले मिल कर एक दूसरे का अभिवादन किया। बाद में इस परिघटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा ने कहा कि वे भावुक हो गए थे, उनकी आँखें नम थी। यह संज्ञान में लेना होगा कि अफ्रीकी संघ को यह सदस्यता भारत के प्रयासों से और उसकी ही अध्यक्षता में प्राप्त हुई है। यह परिघटना केवल बीस देशों के समूह की संख्या को ही इक्कीस नहीं करती अपितु भारत को 'ग्लोबल साउथ' अर्थात् विश्व के दक्षिणी हिस्से का अघोषित

अगुआ भी बना देती है।

भारत ने इस आयोजन को और अपनी अध्यक्षता को अवसर के रूप में भी लिया था। यही कारण है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिश्यटिव के विकल्प के रूप मे अब भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने एक समझौता किया है जिसके तहत लगभग छः हजार किलोमीटर लंबे (3500 कि.मी. समुद्री मार्ग सहित) – "भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी)" के निर्माण की घोषणा की गई है। यह गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक विस्तारित होगा। जो घोषणा हुई है उसके अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत दो अलग–अलग गलियारे शामिल होंगे; एक, पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और दूसरा, उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। यह एक दौर में भारत का प्राचीन व्यापार मार्ग भी था जहाँ से हो कर मसाले सारी दुनिया तक पहुचते रहे थे।

इस सम्मेलन के दौरान इस बात पर न केवल दुनिया भर की मीडिया सजग थी अपितु देश के भीतर भी कुछ लोगों द्वारा इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिलेगी अथवा नहीं। इस घोषणापत्र में हस्ताक्षर न हो पाने का अर्थ होता जी–20 शिखर सम्मेलन का बेनतीजा समाप्त हो जाना। रूस–यूक्रेन युद्ध के दृष्टिगत अनेक पश्चिमी देश इस बात पर अड़े हुए थे कि घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से रूस की आलोचना होनी चाहिए। भारत की कूटनीति ने अपनी दक्षता का परिचय दिया, ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जा सका जिसमें प्रत्येक शब्द इस तरह रखा गया था जिससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी, यूक्रेन युद्ध की बात भी हुई लेकिन रूस की आलोचना को इससे पृथक कर दिया गया। ऐसा करना दो–धारी तलवार पर चलाने जैसा

था लेकिन भारत ने यूरोप से भी संबंध साधे और अपने परंपरागत मित्र रूस को भी किसी विपरीत परिस्थिति में नहीं आने दिया।

नई दिल्ली घोषणा पत्र में उल्लेख है कि 'यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।' इसके साथ ही बहुत सटीकता के साथ किया गया यह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है कि 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए।

परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है।' अर्थात् रूस की बात नहीं की गई जैसा पुतिन चाहते थे लेकिन जो यूरोप चाहता था वह भी उल्लेखित हो गया। इसे कहते हैं कूटनीतिक सटीकता क्योंकि यह ऐसा घोषणा पत्र था जिसपर हस्ताक्षर हो सकेंगे इसका विश्वास न अमेरिका को था न ही रूस को था। सम्मेलन के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी कि "नई दिल्ली जी20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है।" स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखाः – 'नई दिल्ली लीडर्स डिक्लरेशन की मंजूरी के साथ ही इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और मनोभाव के साथ हम एकजुट हो कर बेहतर, अधिक समृद्ध और समन्वय भविष्य के लिए सहयोग के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। जी–20 के सभी साथी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए मेरा आभार।'

नई दिल्ली घोषणापत्र जिन बिंदुओं पर केंद्रित है उनमें महत्वपूर्ण है मजबूत, दीर्घकालीक, संतुलित और समावेशी विकास; सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ाना; दीर्घकालीक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता; 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं तथा बहुपक्षवाद को पुर्नजीवित करना आदि। अभी नवंबर तक भारत के पास ही जी–20 समिट की अध्यक्षता है और इस अवधि में विविध आयोजन होते रहेंगे तथापि राष्ट्राध्यक्षों की इस बैठक के बाद भारत यह अनुभूति कर सकता है कि उसने दुनिया के अग्रणी देशों के मध्य अपनी भूमिका भी तय कर ली है। भारत की कूटनीति इतनी सक्षम है कि वह वैश्विक पटल पर भी अनेक विरोधी विचारों के मध्य समन्वयन का कार्य कर सकती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया ने तो भारत का लोहा माना ही है प्रत्येक भारतवासी को भी इससे गर्व की अनुभूति हुई है।

# भारत में जीवन का केंद्र है 'स्त्री'

## ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023'' पर विशेष

**डॉ. प्रताप निर्भय सिंह**
**शोध प्रमुख, प्रेरणा मीडिया एवं शोध संस्थान**

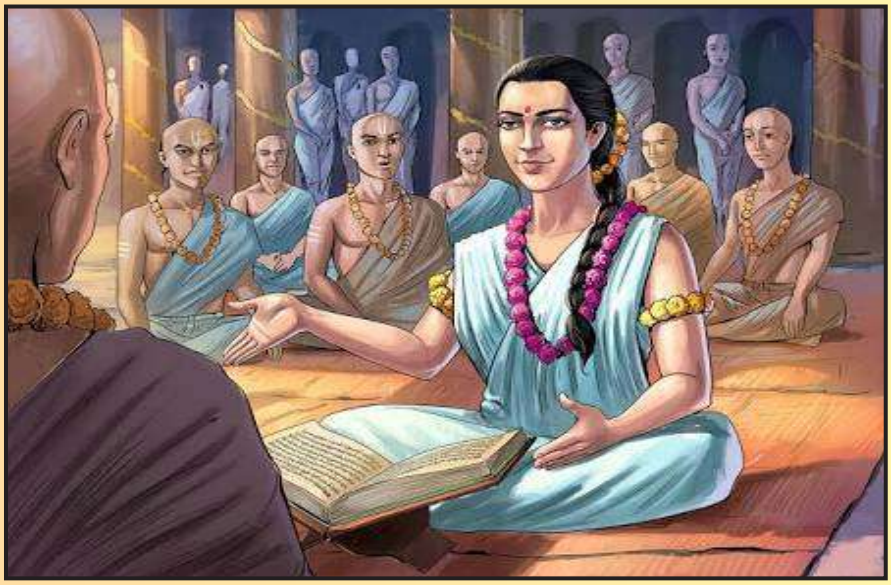

यूँ तो स्त्री विमर्श और वैचारिक मंथन की भारत में लम्बी परम्परा रही है किंतु महिला आरक्षण विधेयक के पश्चात भारतीय समाज में नारी की स्थिति और उनके भविष्य को लेकर मंथन ने जोर पकड़ा है। पिछले 1000 वर्षों की पराधीनताकाल में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों ने जड़ें जमा ली, उनमें से छुआ–छूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति से संबंधित कुरीतियाँ प्रमुख रही हैं। ब्रिटिश समय में तत्कालीन अंग्रेजपरस्त लेखकों के द्वारा यह विचार प्रत्यारोपित किया गया कि भारतीय समाज में स्त्री दीन–हीन और याचक है, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का लाभ लेते हुए तत्कालीन समाज में सक्रिय ईसाई मिशनरीज और भारत विरोधी तत्वों ने भारतीयों को सब प्रकार से दीन–हीन, याचक तथा बौद्धिक रूप से दरिद्र दिखलाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। जीवन के यूरोपीय प्रतिमान को सामने रखकर भारतीय प्रतिमान को विकृत किया गया, भारतीय समाज में भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के प्रति हीन भावना उत्पन्न करने का कुत्सित षड्यंत्र रचा गया। भारतीयों को उनके 'स्वत्व' से विमुख करने में तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक वर्ग सक्रिय हो गया। दुर्भाग्य से 1947 में स्वाधीनता मिलने के पश्चात भी भारत विरोधी तंत्र सक्रिय बना रहा और लेखन और बौद्धिक विमर्श के माध्यम से भारतीय समाज में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के मान बिन्दुओं तथा भारत की सामाजिक परंपराओं पर निरंतर कुठाराघात किया जाता रहा है। मुस्लिम आक्रमणकाल और उसके पश्चात यूरोपीय लुटेरों के द्वारा भारत में स्थापित किए गए उपनिवेश में भारत की आधी आबादी अर्थात मातृशक्ति का सामाजिक और आर्थिक पतन हुआ, ऐसी विद्रूप स्थिति का लाभ लेते हुए यह वर्ग आज भी नारी स्वतंत्रता और नारी अस्मिता के यूरोपीय मानकों पर वर्तमान भारतीय नारियों का आंकलन करता है और विश्व समुदाय के समक्ष भारत में नारी की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। भारत की संस्कृति को स्त्रियों का शोषण करने वाली एवं पुरुष प्रधान संस्कृति के रूप में स्थापित करने वाले तथाकथित नारीवादी बुद्धिजीवियों को भारत की प्राचीन जीवन प्रणाली का अध्ययन करने की महती आवश्यकता है।

वास्तविकता तो यह है कि भारत की संस्कृति में जीवन का उद्गम और अंत स्त्री शक्ति में ही समा जाता है। स्त्री हमारी संस्कृति में पूज्य है, शक्ति के रूप में स्त्री को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला एकमात्र धर्म सनातन हिन्दू धर्म ही है। कदाचित ही कोई भारतीय परिवार ऐसा होगा जिसकी केंद्रीय भूमिका में स्त्री न हो। एक मकान को घर बनाना स्त्री के द्वारा ही संभव है। पर्व त्योहारों एवं उत्सव की पुण्य भूमि भारत में स्त्री सदैव केंद्र में रही है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजन और अर्चन को तब तक पूर्ण नहीं समझा जाता है जब तक पत्नी के रूप में अर्धांगिनी अपने पति के साथ स्थान ग्रहण न करे। माता सीता अपने बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवासकाल में थी तब भगवान राम ने माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर यज्ञ विधान में

स्थान ग्रहण कराया था। प्रभु राम द्वारा सीताजी के त्याग को विधर्मियों ने ऐसा प्रत्यारोपित किया कि भारतीय स्वयं भ्रमित हो गए

महाभारत में कहा गया है कि–

**पूज्या लालयितव्याश्च, स्त्रियो नित्यं जनाधिपः।**
**स्त्रियो यत्र हि पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता।।**
**अपूजिताश्च यत्रैताः सर्वास्तत्राऽफलाःक्रियाः।**
**तदा चैतत्कुलम् नास्ति, यदा शोचन्ति जामयः।।**

– 13.81.5, महाभारत

अर्थात् हे राजन्! स्त्रियों का सदा सत्कार करना चाहिए और इन्हें लाड़ से रखना चाहिए। जहां स्त्रियों का सत्कार किया जाता है वहां दिव्य गुण संपन्न आत्माएं जन्म लेती हैं और जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल होती है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है, वहां पत्नी, बहू आदि स्त्रियाँ शोकमग्न रहती है।

भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, कुटुम्ब की अवधारणा, कुटुम्ब का आधार स्त्री ही है, कुटुम्ब में स्त्री के अवदान के संदर्भ में कहा गया है कि–

**न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।**
**गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते।।**

–12.144.6, महाभारत

अर्थात् भवन को घर नहीं कहते हैं अपितु गृहिणी से ही घर कहलाता है। जो घर गृहिणी से विहिन है, वह तो जंगल से भी बढ़कर सूना है।

मनुस्मृति का निम्न श्लोक तो अत्यंत प्रसिद्द है –

**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता**
**यत्रास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।**

–3.56, मनुस्मृति

अर्थात् जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है उसका सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, वह स्थान मंगलकारी हो जाता है, इसके विपरीत जहाँ नारी का पूजन नहीं होता, वहाँ मंगल भावना से किए जाने वाले सभी कार्य भी असफल हो जाते हैं।

गर्ग संहिता में वर्णन है–

**यद् गृहे रमते नारी लक्ष्मीस्तद् गृहवासिनी।**
**देवता कोटिशो वत्सः न त्यजन्ति गृहं ही तत्।।**

अर्थात् जिस घर में सद्गुण भूषित नारी आनन्दपूर्वक निवास करती है, उस घर में निरंतर लक्ष्मी का वास होता है। हे वत्स! कोटि देवता भी ऐसे घर का त्याग नहीं करते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्रीराम बालि से कहते हैं–

**अनुज वधू, भगिनी, सुत नारी, सुन!**
**सठ कन्या सम ए चारी।**
**इन्हहिं कुदृष्टि बिलोकई जोई,**
**ताहि बधे कछु पाप न होई।।**

अर्थात् छोटे भाई की वधू, बहन, पुत्र की पत्नी, कन्या के समान होती है। इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले का वध कर

देना कतई पाप नहीं है।

स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने का भारतीय परंपरागत उदाहरण सबसे प्राचीन है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव–शक्ति को प्रतिबिंबित कर भारतीय संस्कृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक होने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह विश्व में अतुल्य है।

भारतीय संस्कृति में नारीवाचक शब्दों की बहुलता है जैसे कि भाषा, सभा, संसद, भक्ति, नीति, पृथ्वी, दया, क्षमा, वीरता, कथा, कहानी, तपस्या, पूजा, अर्चना, ज्योति, दीपशिखा, अग्नि, आहुति जैसे अनगिनत शब्द हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं जो अपने आप में मात्र शब्द नहीं है, स्वयं शक्ति का प्रतिरूप हैं, हमने अपनी राष्ट्रीय चेतना को भारत माता कहा है न कि भारत पिता, संपूर्ण विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्र के रूप में स्वयं को एक देदीप्यमान चेतन शक्ति 'भारत माता' के रूप में अंगीकृत किया है।

तथाकथित नारीवादी आरोप लगाते रहे हैं कि भारत में स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा गया, इस दृष्टि से उन्हें भारतीय शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करने की आवश्यकता है।

ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, अदिति, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सार्पराज्ञी, वाक्क, श्रद्धा, मेधा, सूर्या व सावित्री,अहल्या, अरुन्धती, मदालसा जैसी अनेक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। यही सनातन परम्परा आठवी सदी तक स्पंदित थी। आदि शंकराचार्य का जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ तब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने ही न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन किया था, शास्त्रार्थ की मर्यादा का पालन करने वाले ऐसे अद्भुत उदाहरण को हम किसी और संस्कृति में नहीं पा सकते हैं जहां शास्त्रार्थकरने वालों में से किसी एक की पत्नी ही न्यायविद् के रूप में प्रतिष्ठित की जाए।

भारत के अतिरिक्त विश्व का ऐसा कौन सा देश हैं जहाँ संतानें अपनी माँ के नाम से जानी जाती थीं? जैसे कौशल्यानंदन, सुमित्रानंदन, देवकीनंदन, गांधारीनंदन, कौन्तेय व गंगापुत्र, पार्थ आदि। इसी तरह पत्नी का नाम पति से पहले रखने की भारतीय परम्परा है– लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, सीताराम व राधाकृष्ण इत्यादि। क्या किसी अन्य धर्म–संस्कृति में नारी को मान देने के ऐसे उदाहरण मिलते हैं? इसका कोई उत्तर इन तथाकथित नारीवादी बुद्धिजीवियों के पास नहीं है।

जीवनसाथी को अपनी इच्छानुसार चयनित करने एवं वरण करने के लिए भारतीय समाज में स्वयंवर की प्रथा हजारों वर्षों पहले थी, वर्तमान में स्त्री स्वातंत्रय की बात करने वाले बुद्धिजीवियों को स्त्रियों द्वारा अपना वर चुनने की स्वतंत्रता के ऐसे उदाहरण आधुनिक यूरोप में भी नहीं मिलेंगे।

भारतीय ग्रंथों में ऐसी अनेक नारियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने पति के साथ युद्ध में भी भाग लिया। कुन्ती, माद्री, द्रौपदी आदि नारियां शौर्य, पराक्रम और तेजस्विता की पर्याय रही हैं। जिस काल में यूरोप की नारियां घर के बाहर नहीं निकलती थी उस काल में हमारे यहां महान नारियाँ विद्वान उपाध्यिकाओं, प्रशासिकाओं और वीरांगनाओं की भूमिका में सक्रिय थी।

कश्मीर की रानी दिद्दा, काकतीय वंश की रानी रुद्राम्बा, माता मीराबाई, देवलरानी, रूपमती, चारुमती, अक्का महादेवी, रामी जानाबाई, लालदेद, माता सहजोबाई, माता मुक्ताबाई, माता जीजा बाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्मावती, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी ताराबाई, महारानी अब्बक्का, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी चेनम्मा, रानी अवंतिबाई, वीरांगना भाग कौर, ऊदा देवी, रानी वेलु नाचियार, वीरांगना कुइली, बेलावाड़ी मल्लम्मा, वीरांगना दलेर कौर, नायकुरालु नागम्मा जैसी अनगिनत महान नारियाँ हैं जिन्होंने कुशल प्रशासिका, वीर योद्धा, रणनीतिकार या धार्मिक आंदोलन की जनक होते हुए मध्यकालीन भारत में भारतीय अस्मिता और धर्म–संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी अनेक नारियों पर शोध करना शेष है।

इस्लाम के आक्रमण के बाद भारतीय विधर्मियों से कन्याओं की रक्षा करने के लिए और रक्त की शुद्धता बचाने के लिए अल्पायु में बाल विवाह करने का निर्णय हिन्दू समाज को लेना पड़ा, समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा प्रथा आ गयी, इसके पूर्व भारत में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए राजपुतानियों के जौहर जैसे उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलते हैं।

उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन के

काल में भी अनेक क्रान्तिकारी नारियों ने देश की स्वाधीनता हेतु, समाज के नवजागरण हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कादंबिनी गांगुली, स्वर्णकुमारी देवी, भीकाजी कामा, सरला देवी चौधुरानी, ऐनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफअली, सुचेता कृपलानी, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, चंद्रमुखी बसु, आनंदी गोपाल जोशी, प्रतिलता वाद्देदार, दुर्गारानी वोहरा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रभावती देवी, ज्योतिर्मयी गांगुली, लतिका घोष, आशालता देवी, नेली सेनगुप्ता, मातंगिनी हाजरा, रानी गैन्दिन्ल्यु जैसी नारियों के योगदान से हम परिचित हैं किन्तु अनेक ऐसी नारियां हैं जिनका उल्लेख इतिहास के पन्नों में भी नहीं हुआ, ऐसी गुमनाम नायिकाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नई पीढ़ी से उनका परिचय कराना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है।

यह भारत की नारी ही है जिसने विपरीत परिस्थितियों में घर–परिवार की परिसीमा में रहते हुए भी अपनी धर्म–संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और संवर्धित किया, व्रत,पर्व, तीज–त्यौहार के माध्यम से आज भी वे दैनिक जीवन में धर्म–संस्कृति को स्पंदित रखे हुए हैं।

भारतीय समाज में छुआ–छूत, ऊँच–नीच,अशिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का आगमन इस्लाम के आगमन के बाद ही हुआ है, भारत के विरुद्ध स्थापित किये गए भ्रमित एवं असत्य विमर्श के प्रति सचेत रहते हुए शोधपरक स्वाध्याय करना और अपनी नई पीढ़ी को सनातन सांस्कृतिक मानबिंदुओं के प्रति समर्पण और निष्ठा में दीक्षित करने का हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। आजादी का अमृतकाल और सांस्कृतिक नवजागरण काल में यह अनुकूल समय है।

भारत स्वयं को शक्ति स्वरूप मानता है, माँ भारती के रूप में भारत का सांस्कृतिक अस्तित्व शक्ति (स्त्री) प्रधान है, शक्तिविहीन स्त्री विमर्श के सन्दर्भ में भारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की शाक्त चेतना को धारण करने से ही हम भारत की चेतना का साक्षात्कार करने में समर्थ होंगे, इसे अंगीकृत करने से ही हम भारतीय कहलाने के अधिकारी हैं।

# हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान कब ?

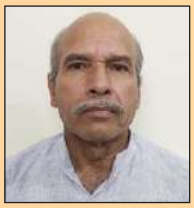

डॉ. नरेन्द्र टोंक
संघ विचारक एवं शिक्षाविद

विश्व में सम्भवतः ही ऐसा कोई देश होगा जो अपने यहां अपनी मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा का दिवस मनाता हो। उन्हें इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनकी राष्ट्रभाषा को वहां के नागरिकों ने आत्मसात किया हुआ है। वहां के सभी राजकार्य और परस्पर व्यवहार वे लोग अपनी भाषा में करते हैं। किन्तु स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हिन्दी है जो अपने समुचित स्थान के लिए आज तक टकटकी लगाए बैठी है। सच पूछो तो हिन्दी अपनों के द्वारा ही अधिक छली गई।14 सितम्बर को हिन्दी दिवस है।देश के सभी कार्यालयों, विद्यालयों, बैंकों में एक दिन,एक सप्ताह और कहीं – कहीं एक माह हिन्दी को समर्पित कर उसका श्राद्ध मनाया जाएगा। श्राद्ध इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वर्ष में एक बार किसी का स्मरण करना श्राद्ध नहीं तो क्या है ?आज हिन्दी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होते हुए भी उसको पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। जिनके मनों पर अंग्रेजी दासता का भूत अभी भी सवार है वो कुतर्क देते हैं कि उच्च शिक्षा और प्रगति बिना अंग्रेजी सम्भव नहीं। उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैं इतना बता दूं कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उनमें से अधिकांश बिन अंग्रेजी और अपनी ही भाषा के बूते विकसित हुए हैं। जर्मनी,जापान, इज़रायल, चीन, फ्रांस, रूस इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आश्चर्य और दुःखद तो यह है कि जो लोग हिन्दी दिवस पर बड़ी –बड़ी गोष्ठियां,कवि सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन्हीं के घरों में यदि झांककर देखोगे तो पश्चिम या अंग्रेजी पसरी मिलेगी उनके बच्चे पश्चिमी और अंग्रेजी के रंग में डूबे मिलेंगे। यहां तक कि हिन्दी शिक्षकों के विवाह जैसे पवित्र और धार्मिक संस्कारों के निमन्त्रण पत्र भी अंग्रेजी में ही छपते हैं।

हैप्पी बर्थडे और गुडमोर्निंग के बिना तो अब गांव के सरकारी विद्यालयों के बालक भी दिखाई नहीं देते।अब वर्तमान केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के चलते अवश्य ही देश क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी के उत्थान की आशा जगी है।

# ट्रूडो की भारत विरोधी मुहीम

**पुनीत अरोड़ा**
**स्वतंत्र विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता**

राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंध नाजुक हो सकते हैं जिन्हें अक्सर सावधानीपूर्वक संभालने और व्यापक संवाद की आवश्यकता होती है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच एक राजनयिक विवाद तब उभरा जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई धरती पर वांछित अपराधी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता के संबंध में विवादास्पद आरोप लगाए। ये आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए थे और इन आरोपों ने भारतीय अधिकारियों को हैरानी और अविश्वास के भाव से भर दिया। आरोप न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक थे बल्कि दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी और सूचना साझाकरण की गुणवत्ता के बारे में भी चिंताएं पैदा करते है। इस घटना न` दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है।

भारत की प्रतिक्रिया : भारत ने कानून के शासन और उचित प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए इन आरोपों का तुरंत खंडन किया। भारतीय अधिकारियों ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयानों पर निराशा व्यक्त की और कनाडा सरकार से कथित घटना से संबंधित कोई सबूत या जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और राजनैतिक चैनलों के माध्यम से स्थिति को हल करने पर केंद्रित थी। परंतु कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके इसके बाद भारत ने भी आक्रमक कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को तुरंत भारत छोड़ने व साथ ही कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा स्थगित करने का कठोर निर्णय लिया।

लेकिन सवाल यह है कि हरदीप सिंह निज्जर जिसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देश की संसद में बोलना पड़ा वो आखिर कौन है। 45 वर्षीय निज्जर पंजाब के जालंधर में भारसिंह पुरा गाँव से था। इसका नाम भारत के शीर्ष 40 आतंकियों में शामिल था। वह आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स (KTS) का सरगना था। राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी ने निज्जर पर 10 लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था। निज्जर कई वर्ष पहले भारत से भाग गया था और अवैध तरीक़े से कनाडा पहुँचा। वह कनाडा की नागरिकता लेना चाहता था लेकिन कनाडाई सरकार ने इससे इंकार कर दिया उसके बाद उसने एक कनाडाई महिला से शादी कर ली। ऐसा करने की वजह कनाडा की नागरिकता हासिल करना था। भारत ने निज्जर को 2020 में ही आतंकी घोषित कर दिया था, इसकी सूचना कनाडा सरकार को दी गई थी परंतु उसने कोई क़दम उठाना उचित नहीं समझा।

पिछले कई दशकों से ख़ालिस्तान से जुड़ी भारत विरोधी गतिविधियों पर कनाडा ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। कनाडा में सिख प्रवासी काफ़ी संख्या में है,ऐसे उदाहरण है जहाँ इस समुदाय के कुछ व्यक्ति भारत विरोधी व अतिवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सिख अलगाववादी या खालिस्तानी उग्रवाद के समर्थक के रूप में देखा जाता है,जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज्य की माँग करता है।यह अलगाववादी खुलेआम भारत को खंडित करने व भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं।कनाडा में मंदिरों को निशाना बनाने के साथ साथ हिंसा में भी

लिप्त रहते हैं।इन आतंकियों पर अंकुश लगाने की अपेक्षा कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रोत्साहन देता रहा है।

**कनाडा में भारत विरुद्ध गतिविधियां :** 1. कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन और रैलियाँ हुई जहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडे और चरमपंथी माने जाने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें प्रदर्शित की। ऐसे ही एक प्रदर्शन में कनाडा के ब्रैंपटन शहर में पांच किलोमीटर लंबी एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान एक चलती हुई गाड़ी पर इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य दिखाया गया। जिससे भारत और कनाडा के बीच तनाव पैदा हुआ।

2. भारत में सिख अलगाववादी समूहों या व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए कनाडा में धन उगाही के प्रयास होते रहे हैं जिसकी कनाडाई अधिकारियों ने जाँच भी की है।

3. कुछ व्यक्तियों पर साहित्य, भाषणों या ऑनलाइन सामग्री के द्वारा चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के मामले भी संज्ञान में आए हैं।

कनाडा की इसी निरंकुशता व ख़ालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने की नीति के कारण 1985 में एअर इंडिया के कनिष्क विमान को इन अलगाववादियों ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। 329 लोगों को इस घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दशकों तक चली जाँच के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस मामले में कनाडा सरकार का रवैया बेहद आपत्तिजनक था और आरोपियों के प्रति उसका रुख़ अत्यंत नरम।

अब तक कनाडाई सरकार ने लगातार कहा है कि वह किसी भी प्रकार के उग्रवाद या आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से कनाडा में चरमपंथ तेज़ी से बड़ा

है।प्रवासी सिखों के लिए कनाडा पसंदीदा जगहों में से एक है, परंतु एक देश में इकट्ठे होते ख़ालिस्तान समर्थक भारत के लिए चिंता का विषय है। इसमें कनाडा के आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड (आईआरबीसी) की नीतियां विशेष रूप से ज़िम्मेदार है। यह बोर्ड किसी भी अप्रवासी को शरणार्थी का दर्जा दे देता है जो यह कहे कि वह खालिस्तानी है और अपने राजनीतिक विचारों के कारण उसे भारत में ख़तरा है।

पाकिस्तानी संयोजन : जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद व पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर भारत द्वारा लगाम लगाए जाने के कारण पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई जैसे बेरोज़गार हो गई है, और भारत को अस्थिर करने के लिए ख़ालिस्तान आंदोलन को हवा दे रही है। यह पाकिस्तान की ही भू राजनैतिक परियोजना है। वरिष्ठ पत्रकार टेरी मिलेवक्सी की "ख़ालिस्तान ए प्रोजेक्ट ऑफ़ पाकिस्ता" शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट है, जिसमें ख़ालिस्तान आंदोलन की तहक़ीक़ात की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि ख़ालिस्तान आंदोलन का बीज पाकिस्तान ने ही बोया था और वही आज तक इसे पोषित कर रहा है। इतना ही नहीं ग्रीक सिटी टाइम्स की एक स्वतंत्र जाँच के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की भारत को कमज़ोर करने के लिये एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और इस्लामाबाद द्वारा रचित प्रोजेक्ट K2 (कश्मीर–ख़ालिस्तान) पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इस योजना को पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई ने नब्बे के दशक में तैयार किया था। पाकिस्तान अब अच्छी तरह से जान गया है कि कश्मीर में उसकी चाल कभी सफ़ल नहीं होने वाली। ऐसे में वह खालिस्तानी आंदोलन को परोक्ष रूप से सहायता दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के अनेक जगहों पर सिर उठा रहा खालिस्तानी आतंकवाद इसी का उदाहरण है।

भारत पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर लगातार हर मंच से ऐसे देशों पर सख्ती की बात करता रहा है जो आतंक को बढ़ावा देने के लिए अपनी ज़मीन का उपयोग होने दे रहे हैं। भारत पहले भी कई बार अलगाववादियों की सूची और सबूत कनाडा सरकार को भेज चुका है।ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत विरोधी ताक़तों का समर्थन कर इस बार प्रधानमंत्री ट्रूडो एक बड़ी मुश्किल में फँस गये है।कनाडा ने "फ़ाइव आई इंटेलिजेन्स अलाइयन्स" यानी यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेल्या और न्यूजीलैंड के साथ ये मामला साझा किया है। परंतु इन देशों की तरफ़ से या तो कोई बयान नहीं आया है या फिर सतर्क बयान आया है।जबकि ऐसे आरोपों पर यह देश अन्य देशों पर कार्रवाई कर चुके हैं। परंतु यह भारत की सफ़ल कूटनीति का ही प्रमाण है की इस मामले में यह शांत है।

# 'मणिपुर घटना : शांति के प्रयास और भविष्य की सीख'

**मनोहर दान, शोधार्थी**
**मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्याल, उदयपुर**

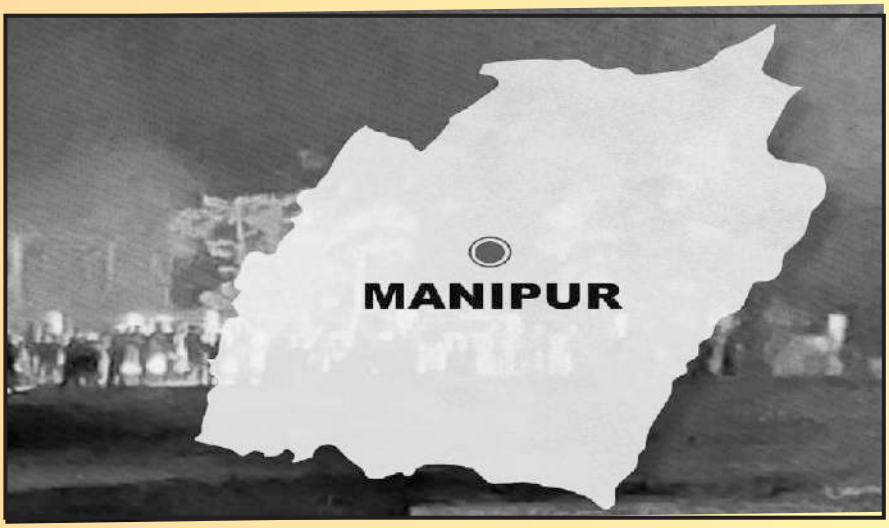


मणिपुर घटना को लगभग पाँच महीने होने को है, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर,अब राज्य शांति की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दृश्यों और आंकड़ो ने हमारे समक्ष कई जटिल अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न किए है।

पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण और सीमा प्रहरी के रूप में मणिपुर राज्य, भारत का मणि अर्थात 'आभूषण की भूमि' है।

मणिपुर अपनी सुंदर घाटियों, हरित पहाड़ियों, मनोरम लोकनृत्यों, बेजोड़ हस्तशिल्प और विभिन्न जनजातीय रिवाजों के कारण भारत में अपना विशेष स्थान रखता है।

इसी साल मई, 2023 के प्रथम सप्ताह में मणिपुर के अंदर फैली नृजातीय हिंसा ने मणिपुर की शांति और प्रगति को बाधित किया। यहाँ पर हत्या, आगजनी, पलायन और महिला अत्याचार के मामले सामने आए है। मणिपुर के सबसे बड़े गैर–जनजाति समुदाय मैतेई एवं कुकी–नागा जनजाति समूह के मध्य उपजे अविश्वास और हिंसा–प्रतिहिंसा की घटनाओं ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती उत्पन्न की है।

**मणिपुर हिंसा के अंतर्निहित कारण :-** पूर्वोत्तर राज्यों में आज़ादी के बाद से उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। मणिपुर राज्य में भी नब्बे के दशक में भी हिंसा का वातावरण रहा था। 1993 में 700 से अधिक लोगों की हिंसक घटनाओं में मृत्यु हुई थी। 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत अवसरंचना का निर्माण और उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते के अथक प्रयासों के बाद उग्रवाद को नियंत्रित करके यहाँ पर प्रगति के पथ को प्रशस्त किया है।

भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त, 2023 को लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर बोलते हुए,मणिपुर हिंसा के कारणों को देश के समक्ष रखा। इस क्रम में उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के आदेश को प्रमुख कारण माना है जिसमें वहाँ के सबसे बड़े मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए सरकार को निर्देशित किया था। इस लंबित न्यायिक निर्णय ने मणिपुर हिंसा में चिंगारी का काम किया। इस फैसले के कारण कुकी और नागा जनजातियों मे यह बात फैल गई कि मैतेई समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है जिसके कारण दोनों समुदायों में परस्पर टकराव उत्पन्न हुआ। इसी मुद्दे को लेकर 2 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसी कारण, 3 मई को कई पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिससे दोनों समुदायों में झड़प हुई और हिंसा भड़क गई।

मणिपुर तनाव के अन्य कारणों में 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट भी है, इसके कारण कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने म्यांमार में आंदोलन शुरू किया जिसके फलस्वरूप सैन्य शासकों ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के साथ उनकी सीमा पर कोई बाड़ नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में कुकी व अन्य शरणार्थियों का मणिपुर में प्रवेश हुआ, बदलती डेमोग्राफिक संरचना ने एक अविश्वास उत्पन्न किया। साथ ही, पहाड़ी इलाक़ों में अफ़ीम की अवैध खेती और गोल्डन ट्रायंगल प्रभाव के कारण यहाँ नार्को– टेररिज्म फैल रहा है जो स्थानीय युवाओं को अनैतिक कार्यों में संलग्न कर रहा है।

इसके अतरिक्त दोनों समुदायों के मध्य परस्पर प्रजातीय भिन्नता,धार्मिक मान्यताओं में अंतर और ईसाई मिशनरियों के प्रवेश,भारत विरोधी नॉन स्टेट एक्टर्स एवं विदेशी तत्वों की भूमिका ने इस समस्या को जटिल बना दिया।

**शांति बहाली के लिए सरकार के सशक्त कदम –**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है की

'मणिपुर में धीरे–धीरे शांति लौट रही है'। उन्होंने 4 मई की महिला अत्याचार घटना की भर्त्सना करते हुए सख्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से अपील की है। भारत सरकार द्वारा जांच आयोग गठित करना, उच्च स्तर पर प्रशासन को परिवर्तित करना तथा केंद्रीय बलों की त्वरित तैनाती राज्य में हिंसा रोकने की दिशा में कारगर क़दम थे। सरकार द्वारा दोनों समुदायों के लीडर्स के साथ वार्ता का क्रम जारी रखा हुआ है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का 23 दिन प्रवास भारत सरकार की इस मुद्दे के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा हजारों एफआईआर दर्ज करके, असामाजिक तत्वों को गिरफ़्तार करके हिंसा रोकने का भरसक प्रयास किया है। इसके साथ ही बफ़र जोन का निर्माण,सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती जैसे कार्य किए जा रहे है।

फ़ेक न्यूज़ को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया जा रहा है वहीं सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग का कार्य आरंभ किया गया है जिसके आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में दिए गए है, 2022 में सरकार द्वारा 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग की थी अब 60 किलोमीटर की फ़ेंसिंग निर्माणाधीन है। गृहमंत्री द्वारा मणिपुर राज्य के निवासियों से शांति की अपील की है वहीं विपक्ष द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने की आलोचना की है।

**भविष्य के लिए सबक और सुरक्षा रणनीति–**

कहा जाता है कि हिंसा, प्रतिहिंसा को जन्म देती है। हिंसा राष्ट्र की शांति और उसके विकास को बाधित करती है तथा नागरिकों में अविश्वास उत्पन्न करती है। इसके साथ ही ये व्यापक आर्थिक क्षति, आंतरिक विस्थापन, महिला अत्याचार और आंतरिक सुरक्षा का संकट उत्पन्न करती है।

इसलिए बहुआयामी उपायों के साथ इस परिस्थितिजन्य घटना से निपटना चाहिए। सर्वप्रथम दोनों समुदायों के मध्य विश्वास बहाली का प्रयास करना चाहिए,जिसमें निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 'अच्छी बाड़े ही अच्छे पड़ोसी बनाती है।' म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम में बदलाव करते हुए स्मार्ट फैसिंग करनी चाहिए ताकि अशांत म्यांमार से जारी अवैध घुसपैठ को रोका जा सके,जिससे राज्य की संस्कृति और जनसांख्यिकीय बदलाव को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को तथ्यात्मक रूप से गलत माना है, और नीतिगत फैसले सरकार पर छोड़ने को रेखांकित किया है। इस तरह कोर्ट को भी संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए।

फ़ेक न्यूज़, इंटरनेट आधारित कट्टरता व ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए सरकारों को बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। केंद्र एवं राज्य की आसूचना एजेंसियों की क्षमता का विकास करके भारत विरोधी तत्वों, हिंसक गैर–राज्य अभिकर्ता तथा संदिग्ध विदेशी राष्ट्र की भूमिका को कम किया जा सकता है।

एक सार्थक रणनीति अपनाते हुए सभी हितधारकों को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली में योगदान देना चाहिए, ताकि कभी ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं हो सके। मणिपुर की शांति, पूर्वोत्तर भारत के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी जो की विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी।

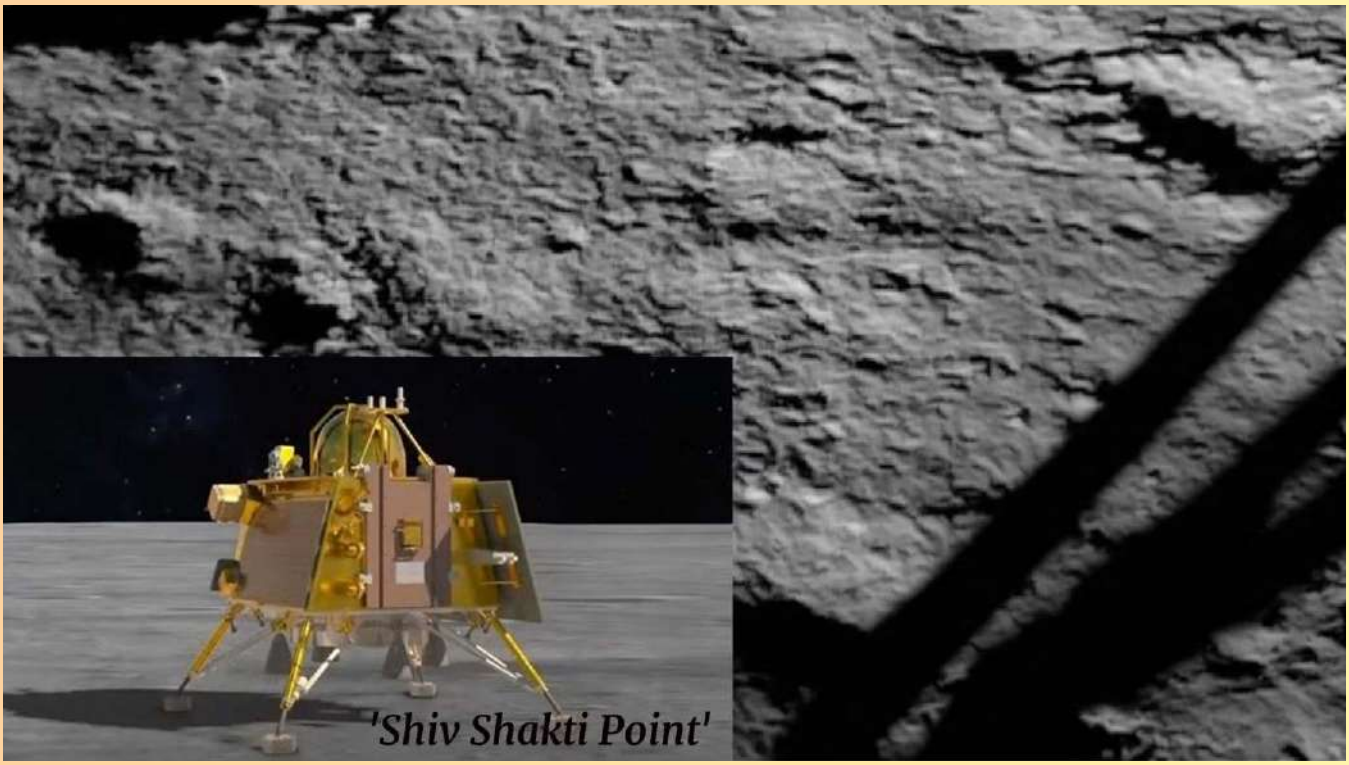


# ‘शिव-शक्ति प्वाइंट’ हिंदू प्रेरणा के हस्ताक्षर हैं, चंद्रमा पर!

**युवराज पल्लव**
**राष्ट्रवादी चिंतक और लेखक**

ब्रह्माण्ड में शिव और शक्ति अध्यात्म की ही नहीं वरन् भौतिक जीवन की गतिशीलता की असीम ऊर्जा का स्रोत है। यही सत्य है और सुंदर भी है। शिव शक्ति से ब्रह्माण्ड चलित होता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार, जहां शिव पुरुष का प्रतीक हैं, वहीं शक्ति प्रकृति का। इन दोनों के संतुलन से ही पूरा ब्रह्माण्ड संतुलित है। पुरुष और प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित होने से ही यह सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। यदि यह सामंजस्य न हो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता। पुरुष और प्रकृति के बीच असामंजस्य असंतुलन पैदा करता है और यह असंतुलन सृष्टि को प्रलय की ओर ले जाता है।

भारत के चंद्रयान–3 अभियान में जिस प्रकार महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने स्त्री शक्ति के रूप में अपनी सहभागिता निभाई है। वह किसी से कम नहीं है। इन्हीं में से एक कल्पना तो इस महत्वाकांक्षी अभियान की डिप्टी डायरेक्टर भी थी। इस प्रकार नारी शक्ति ने दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं और भविष्य की अन्य अनेक चुनौतियों का निर्वहन कर सकने में सक्षम हैं। यद्यपि यह पहली बार नहीं है कि इसरो के किसी अभियान में महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया हो। विश्वभर में चर्चित रहे मंगलयान अभियान को सफल बनाने में भी स्त्री शक्ति का योगदान रहा है। इस प्रकार ये महिला विज्ञानी और इंजीनियर्स उस अवधारणा को खारिज करती हैं कि विज्ञान, तकनीकी, शोध और अनुसंधान जैसे जटिल विषय और चुनौती भरे काम को कर सकने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत ये हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लिखित ‘शिव– शक्ति’ की अवधारणा को साक्षात् करती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 के टच डाउन प्वाइंट को ‘शिव शक्ति नाम बस ऐसे ही नहीं दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश और निहितार्थ छुपा है। जो भारत ही नहीं विश्व को भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और विज्ञानी

अवधारणा को जानने समझने को प्रेरित करता रहेगा। भारत में इस्लामी आक्रमणों के बाद जिस प्रकार नारी के अस्तित्व, स्वाभिमान और उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी। उसकी काली छाया से निकलने में हिंदुस्तानियों ने पाश्चात्य सोच को अपनी प्रेरक शक्ति के रूप में अपनाकर एक नई किस्म की मानसिक गुलामी को ओढ़ना शुरू किया था। जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण और ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान है जो कथित रूप से अबला माने जाने वाली महिला को 'सबला और शक्ति के स्रोत' के रूप में प्रकट करते हैं। यदि आजादी के बाद से भारत का नेतृत्व हिंदुत्व सोच का रहा होता तो जो परिणाम हम आज देख रहे हैं, वह वर्षों पहले हो चुका होता।

यह भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति और सोच ने किया, जो 'भारत को एक खोज' और स्वयं को 'एक्सीडेंटल हिन्दू' मानकर मुगलों और अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाया। उसका दृढ़विश्वास था कि अपनी शिक्षा से वह अंग्रेज और संस्कृति से वह एक इस्लामी है। और इसी मानसिक गुलामी को उसने पूरे भारत पर थोपा। इस प्रकार उसने भारत को, उसके सामर्थ्यवान लोगों को एक अदृश्य मानसिक बेड़ियों में जकड़ दिया था। अपनी हर समस्या के समाधान के लिए ऐसा भारतीय बाहर पश्चिम की ओर ही देखता था।

लेकिन आज मोदी के नेतृत्व में विश्व देख रहा है कि भारत जब अपने 'स्व' को जानकर, समझकर उठ खड़ा हुआ है तो दुनिया उसे अपना नेता मानने में गौरवान्वित महसूस कर रही है। इसी 'स्व' के प्रकटीकरण का बोध कराता है, उन महिला वैज्ञानिकों की वेशभूषा भी। जो चंद्रयान–3 के सफल होने पर पारंपरिक साड़ी पहने, लगे में

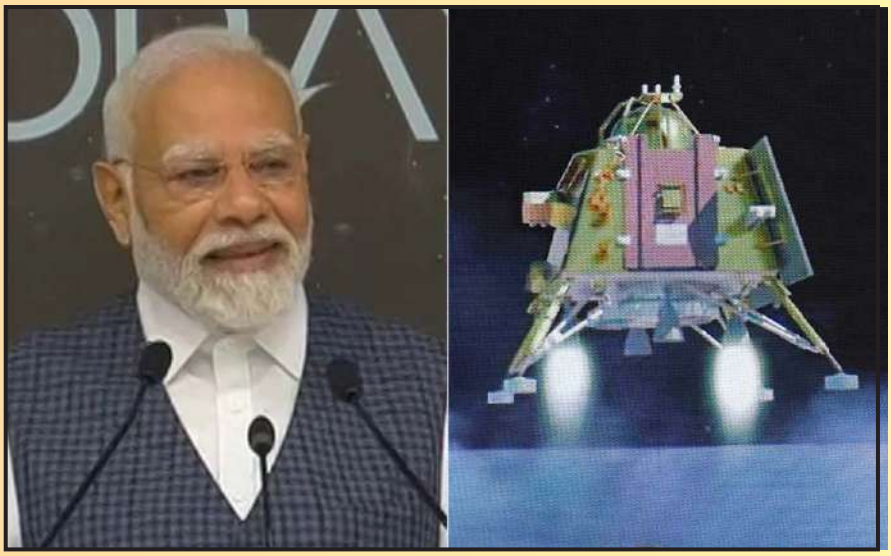

मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर लगा कर पूरे आत्मविश्वास से उत्साहित होकर एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दीं। अन्यथा 'नेहरु सिंड्रोम' का शिकार हमारा उच्चवर्ग साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र को पिछड़ा, गंवार, दकियानुसी और अवैज्ञानिक मानकर एक अलग ही मानसिक गुलामी में जी रहा था। और शेष समाज को भी ऐसे ही जीने को प्रताड़ित भी कर रहा था। लेकिन इसरो की महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी इस विजय और उसके पारंपरिक हिंदू वेशभूषा में उत्साह से भारत में खासकर महिलाओं के बींच स्त्रीत्व के पाश्चात्य कु– प्रभाव को धक्का तो मारा ही है। इसका प्रमाण महिला वैज्ञानिकों को सोशल मीडिया पर पारंपरिक हिन्दू वेशभूषा में देख कथित बुद्धिजीवियों (कुबुद्धिजीवी), के उद्वेलित होने से स्पष्ट है। चाहे जो भी हो 'शिव –शक्ति' प्वाइंट के रूप में भारत ने स्त्री– पुरुष समानता की अपनी हिंदू अवधारणा के हस्ताक्षर तो कर ही दिए हैं।

# हिंदू तीर्थ स्थानों के व्यापारिक प्रतिस्थापनाओं पर मुस्लमान बाहुल्य

**राजेश्वर सिंह 'राजू'**
**महामंत्री, डोगरा संस्था, जम्मू**

भारत विश्व का एक महानतम राष्ट्र है। इसे सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। विविधता में भी एकता इसकी विशिष्ट पहचान है। हर धर्म को मानने वाले इस पावन धरती पर भाईचारे का एक उल्लेखनीय उदाहरण पेश करते हुए यहां पर एक साथ रहते हैं। मेल–मिलाप का एक सबसे बड़ा कारण भी स्पष्ट है कि यहां पर बहुतायत हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की है। अगर इसे हिंदू राष्ट्र ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि दो देशों की थ्योरी पर काम करते हुए अखंड भारत को आगे ही दो भागों में विभाजित करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट कर रख दिया गया था। लेकिन धर्म के आधार पर बंटने के लिए कुछ लोगों ने सहमति नहीं जताई और भारत का ही अभिन्न अंग बने रहने को प्राथमिकता देकर संतुष्ट थे और हैं भी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व भर में उभरा और बाकी सभी के लिए भी प्रेरक बना।

अब सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। हज़ारों वर्षों से अगर यह अपना अस्तित्व बचा कर रख पाया है तो उसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि सनातन धर्म को मानने वाले सदैव दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने को प्राथमिकता देते हैं। यही भाईचारा सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ भी बनाता है। हिंदुओं की सनातन धर्म में गहरी आस्था है। यही आस्था मिलजुल कर जीवन यापन करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करती है। इस भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कभी जम्मू व कश्मीर था, यहां पर विशेषकर कितने ही हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर दूसरे धर्म के लोग भी, जिनमें मुसलमान बहुतायत में हैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाया करते थे। लेकिन आतंकवादियों की धमकियों के चलते और जो भी नरसंहार कश्मीर में हुआ उससे हिंदू वहां से पलायन करने को विवश हुए। अब उन खस्ताहाल होते तीर्थ स्थलों पर पूरी तरह से मुस्लिम लोगों के ही व्यापारिक प्रतिष्ठान रह गए। हालांकि 370 हटने के बाद बहुत सार्थक परिवर्तन आया है और उन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार भी हुआ या हो रहा है।

ऐसा देखने और सुनने में आता है कि

जहाँ–जहाँ भी हिंदू धर्म को समर्पित तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य में पाये जाते हैं। इन तीर्थ स्थलों के कारण वहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करती है, चाहे हरिद्वार हो, राजस्थान के उदयपुर और माउंट आबू के बीच में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाथद्वारा हो, औरंगाबाद का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, रामेश्वर के तीर्थ स्थल हों या काशी – विश्वनाथ, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह सभी तीर्थ स्थलों या उनके आसपास मुस्लिम धर्म के लोगों के व्यापारी प्रतिष्ठान स्थापित हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर की बात करें तो यहां पर ऐसे तीर्थ स्थलों की संख्या अधिक है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पता चलता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा का ही उल्लेख करें तो मुस्लिम व्यापारी इस यात्रा की दिल से प्रतीक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि यात्रा के दौरान उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने का तथा व्यापार के माध्यम से अच्छा खासा लाभ अर्जित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

कश्मीर में जब आतंकवादियों ने अपना कहर बरपाना आरंभ किया तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू रहा करते थे, उन्होंने कश्मीर से पलायन कर लिया। इससे वहां के मुस्लिम बाहुल्य लोगों ने व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हालांकि यह भी सत्य है कि अमरनाथ यात्रा पर अधिकतर ही नहीं बल्कि सारे ही व्यापारिक प्रतिष्ठान मुस्लिम लोगों के हाथों में ही हैं चाहे प्रसाद की दुकानें हों, घोड़े, होटल, टैक्सी, ढाबे या अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए भी उन्हीं पर ही आश्रित रहना पड़ता है।

कश्मीर के गांदेरबल जिला में क्षीर भवानी के नाम से एक सुप्रसिद्ध तथा विश्व विख्यात हिंदू तीर्थ स्थल है। इसका रखरखाव हालांकि धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर के पास है, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर जितनी भी दुकानें या बाज़ार है उन पर आधिपत्य मुस्लिम बाहुल्य का ही है, चाहे वे प्रसाद की दुकानें हो या फिर अन्य आवश्यक वस्तुओं की। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि हिंदू धर्म के लोग आतंकवाद के चलते वहां से पलायन कर चुके हैं।

वहीं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। डल झील के किनारे की पहाड़ी पर निर्मित भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आदिकाल से आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में विद्यमान है। शंकराचार्य में हालांकि कोई बाज़ार वगैरह तो नहीं है लेकिन शंकराचार्य परिसर तक जो फल, दूध, दही या बाकि जो भी आवश्यक सामान जाता है, वह आमतौर पर डल झील के पास के बाज़ार से ही लिया जाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य भी मुस्लिम बाहुल्य समाज को कामकाज करके जीवन यापन करने का साधन उपलब्ध करवाते हैं।

इसी तरह से कश्मीर में ही मातृंडय का सूर्य मंदिर भी मुस्लिम बाहुल्य से घिरा हुआ है और वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मुस्लिम समाज का ही आधिपत्य है। कश्मीर के जितने भी हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है और साथ ही हिंदुओं के पलायन कर जाने से भी यह स्थिति पैदा हुई है, जिसके चलते उस क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मुस्लिम बाहुल्य नज़र आता है।

श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल कटड़ा, केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष माता के दर्शन करने ना केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। नवरात्रों के दौरान तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। हालांकि इसका संचालन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन अधिकतर घोड़ों, पिठ्ठू या पालकी से श्रद्धालुओं को माता के दरबार तक ले जाने का कार्य मुस्लिम लोगों द्वारा ही किया जाता है। माता के चरणों में उनको जीवन यापन के लिए रोज़गार उपलब्ध होता है और यही उनकी रोजी–रोटी का साधन भी है। इसी तरह से शिवखेड़ी में जहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और जिसे एक अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर भी घोड़े वाले मुस्लिम समुदाय से ही हैं।

यह बात स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि व्यापार करने के लिए अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के तीर्थ स्थल पर जाकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रियों को धोखे में रखकर अगर व्यापार किया जाए तो वह किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। अक्सर यह देखने में आया है कि हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों की तरफ़ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिकतर मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। लेकिन उन पर हिंदू नाम लिखे रहते हैं जिससे कि तीर्थयात्री भ्रमित होकर उनसे खाना वगैरह खा सकें या अन्य वस्तुएं खरीद सकें। यह सत्य है कि चूंकि तीर्थयात्री शुद्ध वैष्णो भोजन ही खाते हैं इसलिए वे हिंदुओं द्वारा संचालित वैष्णो ढ़ाबों या होटल रेस्टोरेंट से ही खाना खाने को वरीयता देते हैं। अन्य ढाबों या रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए वे असहज सा अनुभव करते हैं।

व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन किसी को अगर धोखे में रखकर व्यापार किया जाता है तो निंदनीय है, इससे आपसी विश्वास टूटता है। यहां यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि व्यापार ईमानदारी के साथ किया जाने वाला धंधा है जिसे अगर जितनी ईमानदारी के साथ किया जाए तो उतना ही फलता–फूलता है। ऐसा सनातन धर्म की धार्मिक किताबों में भी अक्सर पढ़ने को मिलता है, फिर इमानदारी तो हर धर्म की किताबों में प्रमुखता से बताई जाती है। हर धर्म यही संदेश देता है कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसमें ईमानदारी का बरतना बहुत

आवश्यक है, झूठ और फरेब के सहारे अधिक देर तक व्यापार नहीं किया जा सकता।

अगर यह कहा जाए कि हर एक इंसान का सपना होता है कि पैसा कमा कर अच्छा जीवन यापन किया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से हिंदू तीर्थ स्थलों के पास मुस्लिम बाहुल्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा दे रहे हैं उससे भी यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि व्यापारी के लिए व्यापार ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जिन आस्था स्थलों से जीवन यापन का आधार बनता है, उनके प्रति इज्जत–मान और आस्था का होना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे अधिकतर जो लोग इस धंधे में लगे होते हैं, वे इस बात के प्रति सचेत भी रहते हैं क्योंकि यह उनकी उन तीर्थ स्थलों के प्रति भक्ति भाव ही है जो उनके व्यापार को दिन दूनी–रात चौगुनी तरक्की देता है।

आज जिस तरह से भारत में लव जिहाद या धर्म परिवर्तन के किस्से बढ़ते जा रहे हैं उनसे आपस में विश्वास की भावना की कमी साफ़ झलकने लगती है। यहां तक कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि उक्त तीर्थ स्थल की उक्त दुकान किसी और धर्म के व्यक्ति की है तो वहां से सामान लेने में भी कुछ लोग हिचकिचाने लगते हैं। शायद यही कारण है कि अपने व्यापार को बदस्तूर जारी रखने के लिए कुछ लोग अपनी पहचान छुपा कर भी व्यापार करने को प्राथमिकता देते हैं, जो वास्तव में सरासर गलत है।

यह अटूट सत्य है कि जो भी अपने तीर्थ स्थलों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाता है तो उसके दिलो–दिमाग़ पर अपने देवी–देवताओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है। इसी आस्था के चलते ही उसके मस्तिष्क में और कोई बात घर नहीं करती जब तक उसे उकसाया ना जाए। समाज के दुश्मन या देश विरोधी ताकतें इसी अवसर की तलाश में रहती हैं कि किसी तरह से व्यक्ति के संवेदनशील पक्ष को

झकझोर कर रख दिया जाए ताकि वह संवेदनशीलता की हदें पार करता हुआ अमानवीय बर्ताव करने लगे।

हिंदू तीर्थ स्थलों पर मुस्लिम बाहुल्य व्यापारिक प्रतिस्थापनाओं विषय पर लेख लिखते हुए एक विचार तो दिल में कौंधा था कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वक्त रहते हुए हिंदूओं में अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव पैदा ना किया होता तो धर्म परिवर्तन के चलते हुए आज हालात कुछ और ही विकट स्थिति बयां कर रहे होते। आज जिस तरह से तीर्थ स्थलों के आसपास दूसरे धर्म की आबादी में बढ़ोतरी है वह यही साबित करने में सक्षम है।

आज का ज्वलंत प्रश्न यह नहीं है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किसका अधिपत्य हो बल्कि सुलगता हुआ सवाल यह है कि हम लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के बढ़ते केसों को कैसे रोक पाएं? यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के प्रति निष्ठा भाव रखना ही चाहिए लेकिन किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष की भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई भटक रहा हो तो उसे सही दिशा दिखाना भी धर्म के प्रति समर्पित लोगों का कर्तव्य बनता है। हमारा सनातन धर्म सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है लेकिन उस सहनशीलता में अपनी कमज़ोरी नज़र नहीं आनी चाहिए। जहाँ अपने धर्म या राष्ट्र के प्रति भक्ति या समर्पण की भावना का प्रदर्शन करना हो तो पूरे दमखम के साथ करना चाहिए ताकि मानवता का झंडा बुलंदियों पर लहराता रहे। मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। यह हर्ष की बात है कि सनातन धर्म हमेशा मानव कल्याण की ही बात करता है।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि 'हिंदू तीर्थ स्थानों के व्यापारिक प्रतिस्थापनाओं पर मुस्लमान बाहुल्य', एक लंबी बहस को जन्म देता है। इस पर तर्क–वितर्क हो सकते हैं। लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि अगर यह प्रतिस्थापनाएं हिंदू लोगों के पक्ष में भी चाहे हों तो भी यह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि तीर्थ स्थल लूट–खसूट के केंद्र ना होकर सेवा भाव के साथ चलाए जाने चाहिएं। अक्सर ऐसी लूट–खसूट हर धर्म के तीर्थ स्थलों पर देखने को मिलती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्रद्धालुओं का अपने तीर्थ स्थलों के साथ आस्था का संबंध होता है। जब वे इन स्थलों पर व्यापारी वर्ग से लूटने का अनुभव पाते हैं तो मन में कड़वाहट अवश्य आती है। व्यापारी वर्ग को यह सोच अवश्य रखनी चाहिए कि व्यापार में लाभ तो कमाना ही चाहिए, लेकिन वह लाभ विशुद्ध हो, श्रद्धालुओं की आह से लिपटा हुआ ना हो।

# सनातन धर्म को खत्म करने की महत्वाकांक्षा!

✍ सीमा संघोष डेस्क

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि के पोते और वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए।

उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि "सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा, "सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। इन घृणास्पद बातों का प्रभाव उत्तर तक पहुंच गया। इधर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल RJD के नेता जगदानंद ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा, देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में ऐसी बातों का जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा जाना बढ़ा है। सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? न्यायालय द्वारा हेट स्पीच पर कठोर प्रतिक्रिया आने के बावजूद हिंदु धर्म, हिंदु समाज और सनातन संस्कृति के खिलाफ हेट स्पीच रुक नहीं रही है। न्यायालय भी इसके खिलाफ कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा। जैसा कि वह इस्लाम और ईसाइयत के मामलों में दिखता है। ऐसे में जब शासन प्रशासन और न्यायपालिका भी एक खास रंग में रंगी नजर आए तो इसके पीछे के षड्यंत्र और उसकी गहराई को समझना आवश्यक हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का षड्यंत्र सनातन ने कभी देखा न हो। लेकिन हिंदुओं की समस्या यह है कि जिस क्षेत्र में ऐसा हुआ उसकी या तो उन्हें जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने इसे याद रखना उचित नहीं समझा। यदि उन प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास की ओर निगाह डाली जाए जो अब समाप्त हो चुकी हैं। जिनका स्थान अब ईसाइयत या इस्लामियत ने ले लिया है, तो हम इस प्रकार के षड्यंत्र को भली भांति समझ सकते हैं। इतना ही नहीं यदि हम गोवा जो कभी एक हिंदू बाहुल्य राज्य था, का किस प्रकार ईसाईकरण हुआ यह जानेंगे तो भी बहुत चीजे स्पष्ट हो जाएंगी।

आज ऐसे ही एक षड्यंत्र के विषय में हम जानेंगे। बात करते हैं, 391 ई. की जब ग्रीक रोमन साम्राज्य में बहुदेववाद के पतन और मिस्र और मध्य पूर्व के इसाईकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी विषय पर वर्ष 2009 में अंग्रजी भाषी एक स्पेनिश फिल्म भी बन चुकी है, नाम था अगोरा।

इसमें दिखाया गया था कि एलेक्जेंड्रिया जो तब रोमन साम्राज्य का भाग था, में एक महिला दार्शनिक हाईपिशिया अपने पिता के साथ रहती है। वह मूर्ति पूजक है, देवी– देवताओं में विश्वास करती है और अंतरिक्ष में ग्रहों की

स्थिति पर काम कर रही होती है। लेकिन कुछ लोग उसके काम से खुश नहीं होते। क्योंकि उसके सिद्धांत बाइबिल के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। जिसमें कहा गया है कि सूर्य, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जबकि हाईपिशिया का कहना है कि सूर्य स्थिर है। ये नए ईसाई बने लोग धीरे– धीरे पहले उसका, उसके द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का मजाक उड़ाते हैं, फिर उस समाज की धार्मिक भावनाओं का और देवी– देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। बाद में उन्हें गालियां भी देने लगते हैं, और उस धर्म की मान्यताओं और उसे समाप्त करने की न सिर्फ बात करने लगते हैं बल्कि लोगों से लड़ने– झगड़ने भी लगते हैं। कुछ समय बाद यह व्यवहार इतना बढ़ जाता है कि हाईपिशिया और उसके समाज को आमने– सामने की लड़ाई के लिए निर्णय लेना पड़ता है।

उसके और उसके समाज के लिए असली समस्या सामने तब आती है, जब वे यह देखते हैं कि वो जिस ईसाई मजहब को अप्रभावशाली, अल्पसंख्यक समझ रहे थे, दरअसल, उनका अधिकांश समाज ईसाई बन चुका है। ऐसे में उनके पास अपनी जान बचाने के लिए भाग कर छुपने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि इस लड़ाई में बहुत लोग मार डाले जा चुके होते हैं। शेष कुछ ईसाई मजहब अपना लेते हैं। हाईपिशिया भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करने और ईसाई मजहब स्वीकार न करने के कारण सार्वजनिक रूप से नग्न कर पत्थरों द्वारा मार डाली जाती है। लेकिन कथित शांति और करुणा वाले ईसाई इतने से संतुष्ट नहीं होते और उसकी आंखे नोंच कर निकाल ली जाती है, अंग– प्रत्यंग क्षत विक्षित कर दिए जाते हैं।

क्या भारत में ईसाई मिशनरियां प्राचीन रोम, ग्रीस, यूरोप और अफ्रीका की ईसाइयत से पूर्व की ऐसी ही परिस्थितियां खड़ी नहीं कर रही? जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से ईसाइयत पूर्व की बहुदेववादी मूर्तिपूजक धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जाती थी, उसे भेदभावपरक, समाज के लिए आधुनिक होने के रास्ते का रोड़ा इत्यादि बता कर समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। जो काम तब के शासक वर्ग, पुजारी वर्ग ने किया वैसा ही काम आज के कुछ राजनेता और भगवा वस्त्र धारी छद्म ईसाई कर रहे हैं। जो खुल कर सनातन धर्म के विरोध में ऊल– जलूल बयान देते रहते हैं। या फिर यह महज एक इत्तेफाक है?

वास्तव में यह नेता जो कर रहे हैं वो यह जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कितने प्रतिशत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख छद्म ईसाई (जिसे क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है) बन चुके हैं। ताकि यदि वे सक्षमशील स्थिति पहुंच गए है तो हिंदुओं और सनातन धर्म को समूल समाप्त किया जा सके। और वे ऐसा इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि जब सन् 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे, तो उन्होंने भारत को एशिया में ईसाईयत को फैलाने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन बताया था। इस प्रकार उन्होंने 21वीं सदी में भारत को ईसाई देश बनाने का लक्ष्य दे दिया था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्षों से भारत में 'जोशुआ प्रोजेक्ट' चलाया जा रहा है।

वास्तव में भारत ईसाइयत और इस्लाम के लिए अपने फैलाव का अंतिम चरण है। यूरोप और अफ्रीका पहले ही इनके अधीन आ चुके हैं। अब जिसने भी भारत को अपने अधीन कर लिया संपूर्ण एशिया में उसका ही कब्जा होगा। यह तय है। इसलिए दोनों शक्तियां भारत के बाहर भले ही एक दूसरे के शत्रु हों, किंतु भारत में ये एक होकर अपने अविजित, अभी तक अपराजेय प्रतिद्वंदी हिंदुत्व या सनातन धर्म को समाप्त करने में लगी हैं।

और इस बार इनका हथियार है, अल्पसंख्यक, गरीब–पिछड़े, मानवाधिकार, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी आदि की रक्षा जैसे मूल्यपरक शब्द। क्योंकि हिंदू जो मूलतः मानवतावादी, सहनशील, संवेदनशील है इन झांसों में आ कर इन्हे सत्ता सौंप देने से गुरेज नहीं करता। परिणामतः साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक–2011 जैसे विधेयक लाए जाते हैं जिसमें हर स्थिति में हिंदुओं को ही दोषी सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास होता है। ये लोग 'हिंदू आतंकवाद' की काल्पनिक बात जोर – शोर से उठाते हैं, किंतु बहुदेववाद और मूर्ति पूजकों के खिलाफ लक्षित हिंसा रूपी 'जिहाद' के किताबी आदेश को उचित ठहराने का बेशर्म प्रयास करते हैं।

ऐसे में हिंदुओं के पास अपने अस्तित्व, अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता को बचाने का एकमात्र विकल्प है हिंदुत्व की डोर को कस कर पकड़े रहना और अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना। यदि विकल्प भी चुनना पड़े तो हिंदुत्ववादी विचार को ही चुने। क्योंकि यदि हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता बचती है, तो ही सम्पूर्ण विश्व की संस्कृति, सभ्यता और शांति बची रह सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के लिए हमें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी भारत के ही अंग रहे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को देख सकते हैं।

# रक्षा समाचार

## केंद्रीय गृह मंत्री ने किया इंडो-पाक सीमा का दौरा

भारत पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील इलाकों में गुजरात का कच्छ इलाका भी है। जहां करीब 22 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है, जिसका काफी हिस्सा पानी से डूबा हुआ है। एक बड़े भाग में दलदल (करीब आठ किलोमीटर में) चलना बेहद मुश्किल है। यहाँ एक ओर अगाध जलराशि और दूसरी ओर दलदली जमीन प्रतिकूल माहौल के कारण इस क्षेत्र को 'हरामी नाला' के नाम से जाना जाता है। इस दलदली जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण भी संभव नहीं है। यहाँ मौसम के साथ–साथ भौगोलिक स्थिति पल–पल बदलती रहती है। इसका एक हिस्सा राजस्थान के बाड़मेर को छूता है। समुद्र में ज्वार आने से दलदली जमीन का मिजाज और तमाम दूसरी चीजों की स्थिति बदलती रहती है। इस विषम परिस्थितियों के बीच इस क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थायी निशानदेही मुश्किल हैं। पड़ोसी देश से होने वाले किसी भी घुसपैठ आदि को निर्णय रोकने की पूरी जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है, जिसका निर्वहन वे बखूबी करते हैं। दलदल वाली जमीन पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को गम बूट पहनकर चलना पड़ता है। इस क्षेत्र को अभेद्य

बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के अथक प्रयास से विकास के कई काम शुरू किए गए हैं। इसमें एक आउटपोस्ट टॉवर 1164 का निर्माण कार्य भी है। लगभग साढ़े 9 मीटर ऊंचे इस टावर में अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं जो सीमापार होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को भी कैप्चर कर हमारे सीमा प्रहरियों को सतर्क कर सकेंगे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस टॉवर के बनने से हमारी सीमा की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। जवानों और अधिकारियों का हिम्मत बढ़ाने के लिए श्री शाह ने हरामी नाला का दौरा किया। जमीनी हालात देखकर यहाँ के लिए कई निर्देश दिए।

हरामी नाले पर दुश्मन निगरानी में चूक होने या खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। अब आउटपोस्ट टॉवर के बन जाने से किसी के लिए भी घुसपैठ करना आसान नहीं होगा।

श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल गुजरात के संवेदनशील तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व से जुड़े अनेक संस्थानों की सुरक्षा सजगता व तत्परता से कर रही है। श्री अमित शाह ने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में वे निश्चित रहते हैं क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के पास ये ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा की सीमा सुरक्षा बल –43 डिग्री से लेकर +43 डिग्री तक अलग–अलग तापमान के बीच सीमाओं की सुरक्षा करती है। चाहे सुंदरवन हो, हरामी नाला हो, जम्मू और कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियां हों या फिर कई प्रकार के जलप्रपातों से घिरा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर हो सीमा सुरक्षा बल ने हमेशा अपनी नजर दुश्मन पर रखी है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के पास लगभग 450 से ज्यादा वाटर वेसेल्स हैं और यहां बनने वाली इस सुविधा से इनके रख– रखाव और सजगता को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी।

# सीमाओं को अभेद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता

## कच्छ में श्री अमित शाह ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पड़ोसी देशों से सटी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों व अधिकारियों को पहले से अधिक सहूलियत देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय समय–समय पर काम करता रहा है। इसी कड़ी में 12 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में सीमा सुरक्षा बल के मूरिंग प्लेस का भूमि पूजन और विभिन्न परियोजनाओं का ई–लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल सहित अनेक गणमान्य लोग भी शामिल होकर उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत लगभग ₹250 करोड़ की लागत से एक पूर्णाधिकृत प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स मेस, कैंटीन, परेड ग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, जल यानों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए वर्कशॉप सहित एक अत्याधुनिक यूनिट बनाई गई है। अपने संबोधन में उन्होंने कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जवानों के समर्पण, त्याग और बलिदान को देश की 130 करोड़ की जनता बहुत सम्मान के साथ देखती है। सीमा सुरक्षा बल के पास जल, थल और आकाश तीनों की सुरक्षा करने का सामर्थ्य और हौसला है।

कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वन बॉर्डर, वन फोर्स का निर्णय लिया था। इस निर्णय के कारण हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज को भौगोलिक परिस्थितियों, सीमावर्ती देश के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों और खतरों का मूल्यांकन करना बहुत आसान हो गया। उस समय सीमा सुरक्षा बल को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इस निर्णय को लेने के पीछे बहुत गहरी सोच रही होगी क्योंकि सीमा सुरक्षा बल की सजगता पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं के अनुरूप और इनकी सुरक्षा करने में सक्षम है।

श्री शाह ने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अकेला सीमा सुरक्षा बल ऐसा बल है जिसके पास भूमि और जल सीमाओं की सुरक्षा करने की विशेषज्ञता है और इसका अपना एयर विंग भी है।

# तवांग मैराथन के जरिये भारत ने चीन को दिया स्पष्ट संदेश

तवांग : अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मैराथन का आयोजन कर भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि यह राज्य भारत का गहन अभिन्न हिस्सा है। चीन की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित तवांग शहर में रविवार को सुबह पहली बार मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग–अलग उम्र और क्षेत्र के 2,300 से ज्यादा लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। रिजिजू ने पांच किलोमीटर वर्ग में भाग लिया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। पेमा खांडू ने पांच किलोमीटर के सर्किट को पूरा किया। खांडू ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां मैराथन का प्रायोजक बनने के लिए आगे आ रही हैं। अब हर साल इसका आयोजन किया जाएगा।

यह मैराथन समुद्र तल से 10 हजार फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर आयोजित की गई। इसके साथ ही यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर होने वाली पहली मैराथन बन गई। इस मैराथन का आयोजन भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने खेल कार्यक्रमों का आयोजन कराने वाली कंपनी 'सायरंस स्पोर्ट एलएलपी' के सहयोग से संयुक्त रूप से किया।

आयोजकों ने बताया कि मैराथन के लिए 2,463 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 543 महिलाएं शामिल थीं। मैराथन में कुल 2,343 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 511 महिलाएं थीं। घना कोहरा और कम तापमान भी मैराथन में हिस्सा लेने वालों और स्थानीय लोगों के हौसले को डिगा नहीं पाया मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों में 858 प्रतिभागी सशस्त्र बलों से थे, जबकि भारतीय सेना के 803 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मैराथन में भाग लेने वाले लोगों में से 452 धावक राज्य के बाहर से आए थे। तवांग स्टेडियम से ही मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई और यहीं आकर दौड़ समाप्त हुई। इस दौरान पूर्ण मैराथन (42.195 हाफ किलोमीटर),10 (21.0975 किलोमीटर), किलोमीटर और पांच किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री खांडू ने इस साल जून में की थी।

साभार : दैनिक जागरण

# सीमा संवाद श्रृंखला : रिपोर्ट

**विषय – राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के प्रबंधन का महत्व**

**मुख्य वक्ता : लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी**

**स्थान : दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय**

## प्रांत स्तरीय कार्यक्रम

**संकलनकर्ता :**

**राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी**

**(सदस्य सीमा संघोष संपादकीय टोली, सीमा जागरण मंच)**

दिनांक 28 सितम्बर 2023 को सीमा जागरण मंच द्वारा दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्यारहवां सीमा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि सीमा जागरण मंच द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली में प्रांत स्तर पर हर महीने एक सीमा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

इस बार आयोजित होने वाले सीमा संवाद कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के प्रबंधन के महत्व पर आधारित था। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी मुख्य वक्ता तथा लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली तथा मेजर जनरल आर.पी.एस. भदौरिया ने सहायक वक्ता के रूप में अपने व्याख्यान द्वारा श्रोताओं की वैचारिकी को समृद्ध किया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अधिवक्ता श्री रामचंद्र जी द्वारा की गयी। प्रारंभ में रामचंद्र जी ने सीमा संवाद के पहले के हो चुके व्याख्यान के हवाले से आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता को चिन्हित किया तथा अब तक संपन्न हुए

सभी सफल कार्यक्रम के लिए श्रोताओं और वक्ताओं का आभार भी ज्ञापित किया। स्वागत वक्तव्य के बाद उन्होंने मेजर जनरल आर.पी.एस. भदौरिया को आगे की भूमिका के लिए आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम मेजर जनरल आर.पी.एस. भदौरिया ने मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मां भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके उपरांत मेजर जनरल आर. पी.एस. भदौरिया ने लेफ्टिनेंट जनरल साहनी की सेवा काल में उनके द्वारा अर्जित किए गए बहुत सारे सम्मान और साहसिक कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर श्रोताओं को उनके महत्व के बारे में बताया। इसके बाद जनरल भदोरिया ने लेफ्टिनेंट जनरल साहनी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया।

जनरल साहनी ने सर्वप्रथम सीमा जागरण मंच को उनके इस कार्य के लिए तथा इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। लेफ्टिनेंट जनरल साहनी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत भारतीय सीमाओं के भौगोलिक प्रदेश को मानचित्र के माध्यम

से रेखांकित करके की। उन्होंने भारतीय स्थलीय सीमा और जलीय सीमा तथा उससे सटे हुए भारतीय राज्यों और पड़ोसी देश की भौगोलिक स्थिति पर भी दृष्टिपात किया। क्योंकि विषय एलएसी से संबंधित था अतः आपने भारत की सीमाओं जो की मूल रूप से चीन से संबंधित है उन पर बातचीत शुरू की। चीन से संलग्न सीमा को आपने तीन भागों में बांटकर विषय पर जानकारी दी जिसमें–पहला भाग लद्दाख क्षेत्र से संबंधित था, दूसरा भाग हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों से संबंधित था तथा तीसरा भाग अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से संबंधित था। इस दौरान बात करते हुए उन्होंने बताया कि सन् 1958 में लद्दाख से जुड़ी हुई सीमा की वास्तविक स्थिति क्या थी तथा आज के दौर में वह सीमा कितनी प्रभावित हुई है। मानचित्र में देखें तो एक बड़ा भूखंड जो कि पहले भारतीय भाग का हिस्सा था अब चीन के प्रभाव क्षेत्र में आता है।

इसके पीछे की स्थितियों पर आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से चर्चा की। दुर्गम तथा दुरूह माने जाने वाले इन इलाकों में भारतीय क्षेत्र से पहुंच बना पाना किस तरह से कठिन है इसका दर्शन मुख्य वक्ता ने पीपीटी और विशेष रूप से बनाए गए नक्शे की मदद से कराया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह क्षेत्र अब विवादित है। वास्तविकता तो यह है की दो देशों के बीच में किसी की उदासीनता और किसी की हठधर्मिता एक बड़े क्षेत्र को परेशानी में डाल देती हैं। आपने यह भी बताया कि पहले के समय में जब हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं थी चाहे वह पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो पर भौगोलिक स्थिति इस तरह थी कि भारतीय सिपाही द्वारा पहरा दिए जाने के लिए सीमा रेखा तक पहुंचाने का मार्ग बहुत कठिन और समय लेने वाला था जबकि इसके विपरीत चीन की तरफ से सीमा तक आने का मार्ग ज्यादा सरल और कम समय लेने वाला था। कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर से सिपाही पहरा देने के लिए गए और बहुत दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं आई।

अतः अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां कितनी विपरीत रही होंगी। सीमा रेखा के मध्यवर्ती हिस्सों पर बात करते हुए तिब्बती क्षेत्र के इलाके पर तथा भारत और नेपाल के बीच सीमावर्ती इलाकों में काली नदी को लेकर चल रहे विवाद पर भी प्रकाश डाला। आपने चीन द्वारा की जाने वाली उन तमाम नाकाम कोशिशें जैसे कि चीनी फौजियों द्वारा तिब्बती लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करने की कोशिश तथा तिब्बती लोगों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल करने की कोशिश आदि . .. को बताया जो कि भारतीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम थी। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में चीन से सटी हुई भारतीय सीमा पर चीन की नज़रें क्यों टिकी हुई हैं इसका भी जनरल साहनी ने स्पष्ट उल्लेख किया। आपने डोकलाम तथा अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के संवेदनशील क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाले चीन के प्रयास को भी बताया।

सिक्किम से सटे हुए क्षेत्र की महत्ता पर बात करते हुए आपने बताया कि सिर्फ इस क्षेत्र को प्रभावित कर देने से भारत का अपने देश के उत्तर–पूर्वी राज्यों से संपर्क टूट सकता है तथा यह इलाका 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। चीन

की हमेशा से मंशा भारतीय क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ाने की रही है क्योंकि उससे आंतरिक सुरक्षा में खलल पड़ता है तथा तमाम विकासवादी योजनाओं में रुकावट पैदा होती है। इन सभी मुद्दों की परिचर्चा के दौरान आपने बताया कि कैसे अमेरिका समर्थित चीन का आर्थिक विकास जो की 20वीं शताब्दी के उत्तर में प्रभावशाली तरीके से हुआ उसे चीन कैसे आगे प्रोत्साहित कर रहा है। चीन की रणनीति सिर्फ किसी चीज को सीखने तक ही नहीं रहती बल्कि उससे आगे उस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भी रहती है। इसी के कारण अमेरिकी सहायता को लेते हुए चीन अपने विकास यात्रा पर आगे बढ़ा। बात सीमावर्ती प्रदेश की करें तो भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में उसकी रणनीति उकसाने वाली ही रही है, पहले वह सीमा में कुछ दूर अंदर तक घुस आता है फिर वापस लौट जाता है पर वहां तक नहीं जितनी दूर से वह अंदर आया था, उसके पश्चात वह भारतीय सरकार से बैठकर समझौता करता है। इस प्रक्रिया में वह सहज रूप से थोड़ा–थोड़ा क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है और यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है।

प्योंगयांग और गलवान घाटी में हुए विवाद इसी तरह की प्रक्रिया का नतीजा रहे हैं। अंत में लेफ्टिनेंट जनरल साहनी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समस्या से पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि यह समस्या उनके जन्म से पहले से चली आ रही है और अब उन पर दायित्व होगा कि वह आगे आकर इसको किस तरीके से इसे संबोधित करते हैं। आपने देश के युवाओं से आग्रह किया कि वह जिस क्षेत्र से संबंधित है उसे क्षेत्र में मेधावी बने और विभिन्न माध्यमों से देश की सुरक्षा व अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दें।

अंत में मेजर जनरल भदौरिया ने दौलतराम महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। प्राचार्य महोदया ने लेफ्टिनेंट जनरल साहनी के सारगर्भित वक्तव्य के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पित किया और इस बात की खुशी जाहिर की कि सीमा जागरण मंच के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्रों और छात्राओं को इतनी विशेष और आवश्यक जानकारी ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल साहनी को उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए तथा सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों को इस रोचक वक्तव्य को समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जय हिन्द !!!

# सीमा जागरण मंच, नोएडा विभाग द्वारा आयोजित
# सीमा विमर्श

संकलनकर्ता :
आशीष केसरवानी
शोध छात्र, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी

मादक द्रव्यों के रोकथाम में हम सभी को अपनी–अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। एक अदृश्य युद्ध जिससे हम सभी को अनवरत लड़ना है, यह युद्ध ऐसा नहीं है कि यह किसी बिन्दु पर समाप्त होगा, सतत् ही जागरूक होकर हम सभी को इसका प्रतिकार करना होगा।

पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी प्रतिबद्ध हैं लेकिन इस युद्ध में तब तक हम प्रभावी नहीं होंगे जब तक नागरिक सभी अपने–अपने स्तरों से इसमें नहीं जुटेंगे। "सीमा जागरण मंच, नोएडा विभाग द्वारा 25 सितम्बर 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा मे सायं 3.30 बजे सीमा विमर्श का आयोजन किया गया। इसका विषय था "भारतीय पश्चिमी सीमा के विशिष्ट संदर्भ में मादक आतंकवाद एवं भारतीय सुरक्षा के सरोकार"।

उपरोक्त उद्गार सीमा विमर्श कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, पूर्व इंस्पेक्टर जनरल, पंजाब ने अपने कार्यकाल के विभिन्न अनुभवों को साझा करते हुए यह बताने की कोशिश की कि कैसे एक आम नागरिक जागरूक होकर अपने देश की रक्षा पंक्ति को सक्षम बना सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, पुष्पार्चन एवं माँ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वक्ताओं एवं सदन में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत जहाँ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की कला संकायअध्यक्षा प्रो. बंदना पाण्डेय जी ने किया वहीं नोएडा विभाग के संयोजक डॉ. श्रीश पाठक जी ने, सीमा जागरण मंच के उद्देश्य, कार्यों एवं उसकी सततता के बारे में सभागार को परिचित कराया। सीमाएँ ही हैं जिनसे एक राष्ट्र को आकार मिलता है, ये हमारी अस्मिता से जुड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की सीमा की सुरक्षा से सम्बद्ध हैं।

नोएडा विभाग से सीमांत प्रदेश प्रमुख, पंजाब डॉ. ममता शर्मा जी ने सीमा विमर्श के वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय कराया। विषय प्रवर्तन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. अक्षय कुमार सिंह जी द्वारा किया गया। उन्होंने विषय के अकादमिक पक्षों को चिन्हित करते हुए बताया कि किस प्रकार नार्को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में संबंधित हैं। गौतम

**नोएडा विभाग द्वारा अतिथियों को स्वागत किया गया।**

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रवींद्र सिन्हा जी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि मादक पदार्थों का विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में खासा प्रभाव पड़ रहा है।

कार्यक्रम में विशिष्ट उद्बोधन माननीय ले. ज. डॉ. नितिन कोहली जी, अध्यक्ष, सीमा जागरण मंच, दिल्ली प्रांत ने बहुत ही रुचिकर एवं सूचनापूर्ण रीति से सुरक्षा प्रबंधनों में तकनीक की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के आचार्यों एवं विद्यार्थियों से तकनीक के क्षेत्र में अपना अवदान करने के लिए अपील की। आदरणीय कोहली जी ने विषय पर कई महत्त्वपूर्ण अद्यतन विचार साझा किए और साथ ही सीमा जागरण मंच के अवदानों को स्पष्ट किया। नोएडा विभाग द्वारा इस अवसर पर विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए एक स्टॉल भी स्थापित किया था, जिसे विभाग के सह–संयोजक देशराज मीणा जी एवं आशीष तिवारी जी के नेतृत्व में सज्जित किया गया। सीमा विमर्श कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा विषय को न केवल विद्यार्थियों तक ले जा सकने में सफलता मिली अपितु सीमा जागरण मंच की मूल प्रेरणा से विद्यार्थियों एवं अध्यापकगणों को जोड़ने में भी यह सफल रहा। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आचार्यगण, विद्यार्थीगण, सीमा जागरण मंच के सदस्य उपस्थित रहे। डॉ. नेहा सिन्हा, प्रबोधन प्रमुख नोएडा विभाग एवं मुकेश कुमार भारती, सीमांत प्रदेश प्रमुख, बिहार की विशिष्ट सहभागिता रही और एमिटी विश्वविद्यालय के छात्र भी बड़ी संख्या में सीमा विमर्श कार्यक्रम से जुड़े।